दैनिक समाचार पत्र

देश का दर्पण न्यूज

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली व महाराष्ट्र से प्रकाशित

वर्ष-5, अंक: 97 | जयपुर शुक्रवार ,17 अक्टूबर 2025 | मूल्य : 5.00 पेज:

अब आपके मोबाइल पर डिजिटिल अख़बार
प्रदेश के ताजा समाचार
अपने लेख एवं समचार भेंजे

सम्पादक : उमेन्द्र राजपूत
7014997449, 9636058201
Email : deshkadarpannews@gmail.com
web.: www.deshkadarpannews.co

उपभोक्ता हितों की रक्षा ही हमारी प्राथमिकता: भारत

नई दिल्ली
विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करेगा। मंत्रालय के बयान में खंडन और स्वीकार्यता दोनों नहीं है। इस बयान में उपभोक्ता हितों और ऊर्जा विविधीकरण पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के बयान के बाद प्रतिक्रिया जारी की है। इसमें उन्होंने कहा है कि भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियाँ पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। उन्होंने कहा कि स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं। इसमें हमारी ऊर्जा स्त्रोतों का व्यापक आधार और बाजार की स्थितियों के अनुरूप विविधीकरण शामिल है। जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस पर चर्चाएँ जारी हैं।

रूस और भारत रणनीतिक साझेदारी वैश्विक दबाव से प्रभावित नहीं

रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव का बयान आया है। उनका कहना है कि रूस और भारत रणनीतिक साझेदारी वैश्विक दबाव से प्रभावित नहीं हैं और यह विश्वास की मजबूत नींव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमारी तेल आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है। हमारे व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। वहीं, भारत सरकार सबसे पहले अपने देश के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत की उन्हें जानकारी नहीं है। भारत सरकार की नीतियाँ भारतीय लोगों के हितों को दर्शाती हैं और वे भारत-रूस संबंधों के विपरीत नहीं हैं।

उल्लेखनीय है कि 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत रियायती दरों पर रूसी तेल आयात कर रहा है। इसे आधार बनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले दिनों भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। भारत हमेशा कहता रहा है कि यूरोप और चीन भी रूस से अपनी ऊर्जा जरूरत का बड़ा आयात कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका भी कई जरुरतों के लिए स्वयं रूस पर निर्भर है।

पीएम मोदी ने कहा अब रूस से तेल नहीं लेंगे: ट्रंप

नई दिल्ली
जब से डोनल्ड ट्रंप ने दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है तब से भारत को लेकर उनकी तरफ से दिए जा रहे एक के बाद एक बयान पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को असहज किये हुए है। इस कड़ी में गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यह आश्वासन भारतीय प्रधानमंत्री ने दो दिन पहले उनके साथ हुई बातचीत में दिया है। जबकि भारत सरकार की तरफ से ना तो मोदी और ट्रंप के बीच किसी बातचीत का ब्यौरा गुरुवार दोपहर तक जारी किया गया है और ना ही इस बारे में कोई सूचना है कि रूस से तेल खरीद में कमी कर दी गई है। मीडिया के साथ वार्ता में ट्रंप की तरफ से कही गई इस बात पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक सधी हुई प्रतिक्रिया जरूर जताई है लेकिन इसमें ट्रंप-मोदी के बीच वार्ता या रूसी तेल खरीद में कटौती की कोई बात नहीं है।

रूस ने की भारत से डील, 3-5 लाख मीट्रिक टन केला खरीदने का एलान

नई दिल्ली
रूस के पादप (फाइटोसैनिटरी) स्वच्छता निगरानी संस्था ने कहा है कि रूसी बाजार में भारत केले की आपूर्ति बढ़ा सकता है। रूस में विदेश से कृषि उत्पादों के आयात को मंजूरी देने वाली इस संस्था ने कहा है कि रूस, भारत से पांच लाख मीट्रिक टन तक केले का आयात कर सकता है। संस्था ने कहा कि रूस प्रति वर्ष तीन से पांच लाख मीट्रिक टन भारतीय केले स्वीकार करने को तैयार है। संस्था के प्रमुख सर्गेई डंकवर्ट ने इस संबंध में भारतीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है।

संयुक्त राष्ट्र आज भी 1945 में जी रहा: एस. जयशंकर

नई दिल्ली
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में तत्काल सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यूएन 2025 की नहीं बल्कि 1945 की दुनिया की वास्तविकताओं को दशार्ता है। इस वैश्विक निकाय में सुधार की आवश्यकता अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सुधार की प्रक्रिया का उपयोग एजेंडे को पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है, जिससे ऐतिहासिक अन्याय जारी है। उन्होंने आगाह किया कि जो संस्थान बदलती वास्तविकताओं के

अनुकूल नहीं हो पाते वे अप्रासंगिक हो जाते हैं।

भारत की शांति स्थापना का दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुंबकम' पर आधारित- जयशंकर
जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देशों के प्रमुखों के सम्मेलन (यूएनटीसीसी 2025) को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की शांति स्थापना का दृष्टिकोण उसकी सभ्यता के मूल्यों में निहित है और 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत पर आधारित है। विदेश मंत्री ने कहा, 'यह सैन्य योगदान देशों के इस प्रतिष्ठित समूह को संबोधित करने का एक विशेषाधिकार है, जो शांति के रक्षक और संदेशवाहक हैं। आप एक ऐसे संस्थान की ताकत को दशार्ते हैं, जो लगभग आठ दशकों से संघर्षग्रस्त दुनिया में आशा की किरण के रूप में खड़ा है- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना।" उन्होंने बताया, 'भारत ने सभी समाजों और लोगों के लिए न्याय, गरिमा, अवसर और समृद्धि की लगातार वकालत की है।

प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा की, भगवान का किया रुद्राभिषेक

विशाखापत्तनम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आंध्र प्रदेश दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने नंदयाल जिले में श्रीशैलम स्थित श्री भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा-अर्चना की। भाजपा नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमुरलु (गाय के दूध, गाय के दूध से बनी दही, गाय के घी, शहद और चीनी से बना एक पवित्र मिश्रण) से भगवान का रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री

पवन कल्याण उनके साथ रहे। आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 12 ज्योतिलिंगों में से एक और 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ का सह-अस्तित्व है, जो इसे पूरे देश में अपनी तरह का एक अनूठा मंदिर बनाता है। मंदिर दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री शिवाजी ध्यान केंद्र का दौरा करेंगे, जो एक स्मारक परिसर है। इसमें चार कोनों पर स्थित चार प्रतिष्ठित किलों, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल वाला एक ध्यान कक्ष भी शामिल है।

राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह शुक्रवार को देहरादून में

नई दिल्ली
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह शुक्रवार को देहरादून में होगा। मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी उपस्थित रहेंगे। समारोह में सामुदायिक प्रयास, क्षेत्रीय पहल और पोषण संबंधी गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा।

आजादी के बाद से हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब बन रहे आत्मनिर्भर: राजनाथ

नई दिल्ली
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर को भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस अभियान के दौरान सशस्त्र बलों की ओर से उपयोग किए गए ज्यादातर उपकरण स्वदेशी थे। भारत ने उस बाधा को तोड़ दिया है, जो आजादी के बाद से बनी हुई थी। सरकार ने देश में हथियारों के निर्माण को मजबूत प्रोत्साहन दिया है।

रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ा भारत: राजनाथ
रक्षा मंत्री पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी के दीक्षा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'हमने रक्षा क्षेत्र

में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। शुरूआती दौर में यह मुश्किल था, क्योंकि हम पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर हरे थे। आजादी के बाद से हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। हमारे लिए विदेश से रक्षा उपकरण खरीदना एक जरूरत बन गई थी और स्वदेशी उत्पादन लगभग न के बराबर था। भारत ने अब उस बाधा को तोड़ दिया है, जो आजादी के बाद से बनी हुई थी।' राजनाथ ने कहा, 'हमने देश में ही हथियारों के निर्माण को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया है। यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि देश रक्षा खरीद के मामले में एक सुविधाजनक स्थिति में पहुंच गया था। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदने के आदी हो गए थे।'

शहरी क्षेत्र में 1.41 लाख अतिरिक्त नए घरों को मंजूरी

परिवारों को पक्के घर बनाने या खरीदने में 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद मिलती है

नई दिल्ली
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 1,41,942 नए घरों को मंजूरी दी है। इसके बाद योजना के तहत कुल स्वीकृत घरों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई है। मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भी शामिल हुए।
यह आवास असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान,

तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों लिए होंगे। बैठक में सचिव ने कहा कि घरों का निर्माण ऐसी जगहों पर होना चाहिए जहां सड़क, सार्वजनिक परिवहन और अन्य बुनियादी सुविधाएं हों ताकि लोग जल्दी अपने घरों में रह सकें। इन अतिरिक्त आवासों की मंजूरी में महिलाओं के लिए 76,976 घर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 13,509 घर और ट्रांसजेंडर के लिए 7 घर मंजूर किए गए। अनुसूचित जाति के लिए 29,131, अनुसूचित जनजाति के लिए 6,561 और ओबीसी के लिए 74,291 आवास मंजूर किए गए। अब पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत कुल 6.31 लाख घर केवल महिलाओं को दिए गए हैं, जिनमें विधवा, अलग रह रहीं या अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडरों को 163 घर और वरिष्ठ नागरिकों को 1.04 लाख घर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत परिवारों को पक्के घर बनाने या खरीदने में 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद मिलती है।

सीजेआई पर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर के खिलाफ होगी अवमानना की कार्यवाही, एजी ने दी सहमति

नई दिल्ली
चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलेगी। अटार्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमण ने कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर अपनी सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। विकास सिंह ने कहा था कि जूता फेंकने की घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वकील राकेश किशोर को कोई पछतावा नहीं है। वकील राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंका था, लेकिन जूता चीफ जस्टिस के पास नहीं पहुंच सका। जब उसने चीफ जस्टिस की तरफ दोबारा जूता फेंकने की कोशिश की, तो कोर्ट रूम में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस जब उसे कोर्ट रूम से ले जा रही थी, तो उसने जोर से बोला "सनातन धर्म का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।" राकेश किशोर की उम्र 71 साल है। वह चीफ जस्टिस गवई के उस बयान से आहत था, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी। इस घटना के बाद वकील संगठनों ने इसकी निंदा करते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया था।

नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला, 'सरकार के पास भर्ती की योग्यता तय करने का अधिकार'

नैनीताल
हाई कोर्ट ने गन्ना पर्यवेक्षक के 78 के पदों पर भर्ती मामले में एकल पीठ के निर्णय को पलटते हुए कहा कि भर्ती एजेंसी का काम परीक्षा आयोजित करना व परिणाम घोषित करना है जबकि भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अर्हता तय करने का अधिकार नियोक्ता या राज्य सरकार को है। कोर्ट ने साफ किया कि राज्य लोक सेवा आयोग को नियोक्ता के निर्णय का पालन करना होगा।
कोर्ट के निर्णय से ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने 2023 में गन्ना पर्यवेक्षक के 78 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चयन रद कर दिया था। इन अभ्यर्थियों के मामले सील कवर में बंद किए गए थे।
दरअसल उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 2022 में गन्ना पर्यवेक्षक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया था। सरकार के गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा शैक्षिक योग्यता संबंधी अस्पष्टता पर अपना रुख स्पष्ट करने के बाद भी यूकेपीएससी ने नवंबर 2023 में तीन वर्षीय कृषि अभियंत्रण डिप्लोमाधारकों का चयन रद कर

दिया था। इसके बाद सफल 11 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत नहीं देते हुए भर्ती रद करने के आयोग को निर्णय को यथावत रखा। दरअसल काशीपुर निवासी मनाली चौधरी तीन अन्य का भी इन पदों पर चयन हुआ था। दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, उनके पास कृषि अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा होने के कारण उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया।
नवंबर 2023 में आयोग ने गन्ना पर्यवेक्षक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विसंगति के संबंध में नियोक्ता से स्पष्टीकरण मांगा। सेवा नियमों के अनुसार, इस पद के लिए आवश्यक योग्यता कृषि में दो वर्षीय डिप्लोमा है, लेकिन हाई स्कूल के बाद कृषि डिप्लोमा (कृषि अभियांत्रिकी) तीन वर्षीय होता है, तो क्या तीन वर्षीय डिप्लोमा मान्य होगा या नहीं? सरकार की ओर से बताया गया कि उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड कृषि अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्रदान कर रहा है, इसलिए दो वर्षीय डिप्लोमा या तीन वर्षीय डिप्लोमा कानूनी रूप से स्वीकार्य है। इसके बाद भी आयोग की ओर से कहा गया कि सेवा नियमों में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और अपीलकताओं के मामले को दस्तावेज सत्यापन के चरण में खारिज कर दिया गया था और केवल चयन से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है।

'50% वाली लिमिट याद रखिए...', ओबीसी कोटे को लेकर तेलंगाना सरकार झटका

नई दिल्ली
तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, या डइउ, समुदायों के लिए बढ़े हुए रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट के अंतरिम स्टे को चुनौती दी गई थी।दरअसल, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। रेवंत रेड्डी की सरकार के इस फैसले को इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च

न्यायालय के फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी गई थी। लेकिन यहां से भी राज्य की रेड्डी सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करने के साथ शीर्ष न्यायालय ने तेलंगाना सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने हाल में ही ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। विधानसभा में इसको लेकर एक प्रस्ताव भी लाया गया था। इसको विधानसभा से पारित कर दिया गया। हालांकि, कांग्रेस सरकार के इस कदम के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई और आरक्षण सीमा को बढ़ाने को चुनौती दी गई। इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि जाति आधारित आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना होगा।

सट्टा कांड को लेकर पंजाब पुलिस के डीआईजी गिरफ्तार

रूपनगर
पंजाब पुलिस के डीआईजी रोपड़ रेंज हर चरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी सट्टा मामले से जुड़ी बताई जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीआईजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया

है।
रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरन सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार, मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप कारोबारी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। सीबीआई टीम ने भुल्लर को मोहाली से हिरासत में लिया।

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने ग्रामीण सेवा शिविरों का किया निरीक्षण

पाली/सुमेरपुर, 16 अक्टूबर । पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गुरूवार को पाली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोरटा एवं सलोदरिया के ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन किया। कोरटा / सलोदरिया के ग्रामीण सेवा शिविर में मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने अवलोकन कर विभिन्न विभागों के काउंटरों का निरीक्षण किया तथा वहां चल रही गतिविधियों की अधिकारियों से जानकारी ली। श्री कुमावत ने प्रत्येक विभाग की स्टॉल पर जाकर अधिकारियों और ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होनें सम्बंधित अधिकारियां को निर्देश दिए कि वे इन शिविरों में परिवेदनाओं को गंभीरता से सुने और उनका त्वरित निस्तारण कर सम्बन्धित को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि राज्य की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम छोर तक पहुँचे और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे वंचित न रहे। सेवा शिविरों के माध्यम से शासन और प्रशासन जनता तक सीधी पहुँच बनाकर पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा इन शिविरों के माध्यम से आमजन की लंबित समस्याओं का निस्तारण कर उन्हे विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप इन ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कर त्वरित राहत दी जा रही है। शिविरों में आम नागरिक केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि आमजन अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को इन शिविरों तक लाएं, जिससे उन्हें योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

कुमावत ने कहा कि इन सेवा शिविरों में 16 विभागों को शामिल किया गया है, जहां सम्बंधित विभाग के अधिकारी न केवल योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं बल्कि आमजन की लंबित समस्याओं का भी त्वरित निस्तारण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा भी यही है कि कई बार आमजन को अपने-अपने छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटना पड़ता है, इसलिए एक ही मंच पर और एक ही स्थान पर सभी विभाग समन्वय के साथ आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करें।

ग्राम सलोदरिया में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणधीन 75000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी का निरीक्षण किया गया मौके पर गुणवत्ता व निर्माण सम्बन्धित जानकारी ली साथ ही समय पर गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े काम जैसे नाम शुद्धिकरण, नामांतरण, बंटवारा विवाद आदि काम वर्षों से अटके हुए हैं, जिनका त्वरित निस्तारण इन शिविरों में हो रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र कृषि और पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां की अधिकांश आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है इसलिए उन्होंने इन विभागों की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने पशुपालकों से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के लिए 1 अक्टूबर, 2025 से मंगला पशु बीमा योजना का पंजीयन चालु कर दिया गया है इसलिए अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएं। कार्यक्रमों में मंत्री श्री कुमावत ने पशुपालकों को मंगल पशु बीमा योजना की पॉलिसी, आवासीय पटटों का भी वितरण किया।

शिविरों में ये रहे मौजूद

गजेन्द्रसिंह सरपंच कोरटा ,पूनमसिंह परमार जिला उपाध्यक्ष , जोगाराम रोहिन , शेरसिंह उप सरपंच कोरटा , सलोदरिया सरपंच परबतसिंह राणावत, दुदाराम माली उप सरपंच ,महेंद्रसिंह , कालूराम कुम्हार उपखण्ड अधिकारी ,प्रमोद दवे विकास अधिकारी पंचायत समिति , दिनेश आचार्य तहसीलदार खेमराज बेरवा सहायक अभियंता जलदाय विभाग आदि मौजूद थे।

जिले में 60 दिवसीय "टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन - 3.0" के अंतर्गत आयोजित होंगी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां

अजय सिंह (चिंटू)

जयपुर : "टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 3.0" की 60 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत जिले में तम्बाकू निषेध के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

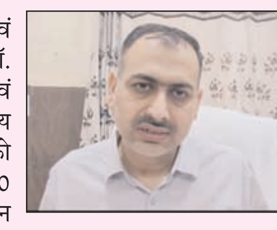

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 60 दिवसीय "टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 3.0" आगामी 08 दिसंबर,2025 तक संचालित किया जाएगा।

"टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 3.0" की 60 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत जिले में अन्य तम्बाकू निषेध गतिविधियों के साथ ही जन-जागरुकता कैम्पेन का आयोजन किया जाएगा। इसमे कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित स्थानों पर तम्बाकू का विक्रय-सेवन पर रोक लगाने के लिए चालान की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सामुदायिक स्तर पर इसके प्रति जन-जागरुकता विकसित करने संबंधित विविध गतिविधियां संचालित की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में स्कूलों, ग्राम पंचायत भवनों, शैक्षणिक- चिकित्सा संस्थानों इत्यादि को तम्बाकू मुक्त करने के लिये निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कोटपा उल्लंघन पर चालान कार्यवाही, ग्राम, ब्लॉक व जिला स्तर पर विद्यार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, नारा लेखन, जिला व ब्लॉक स्तर पर रैलियों का आयोजन कर तम्बाकू के दुर्व्यसन के प्रति आमजन को जागरूक किया जाएगा।

जोधपुर-जैसलमेर हाइवे बस दुखान्तिका

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर से जोधपुर आ रही एसी स्लीपर बस में आग लगने से हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्हें पूरी मदद देने और घायलों के हरसंभव उपचार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जिन परिवारों में 3 या अधिक लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना में हुई है, उन परिवारों को 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। गम्भीर घायलों को 2-2 लाख रुपये एवं अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है।

पीआरकेएस प्रतिनिधि मंडल ने महाप्रबंधक से मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं से कराया अवगत

मसरुर अहमद - संवाददाता, सीवान । पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ की तरफ से राम प्यारे शर्मा (संयुक्त मंडल मंत्री) पीआरकेएस वाराणसी मंडल की अगुवाई में वाराणसी मंडल के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर से मुलाकात कर कर्मचारी की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। जिसमें वरिष्ठ लोको पायलट से लोको पायलट का प्रमोशन अति शीघ्र कराया जाए, चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मचारी एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों की कमी को शीघ्र दूर किया जाए, गैंग हटो की स्थिति जर्जर है, जहां पानी वह विद्युत की भी व्यवस्था नहीं है इसी तरह 90 प्रतिशत इंजीनियरिंग, गेटों पर भी आवास नहीं है अतः गैंग हटो की

रिपेयरिंग, विद्युत, पानी एवं गैंगो पर आवासों का प्रबंध कराया जाए। साथ ही 12 घंटे के ड्यूटी रोस्टर में 2 दिन का विश्राम दिया जाए, संरक्षा कोटि के पदों के अभ्यर्पण पर रोक लगाया जाए एवं संरक्षा संवर्ग (गार्ड) के रिक्त पदों (कांटा वाला, ट्रैकमैन) को शीघ्र भर जाए। ट्रैक मेंटेनरों को साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए, कांटा वाला संवर्ग को 12 घंटे रोस्टर के स्थान पर 8 घंटे की ड्यूटी रोस्टर को लागू कराया जाए तथा दो दिन का विश्राम दिया जाय। वाराणसी मंडल में रेलवे आवास की स्थिति काफी जर्जर है एवं बरसात में वाटर लीकेज सफाई व्यवस्था भी बहुत खराब है जिसे सुधार करने का आदेश दिया जाए, ट्रैक मेंटेनरों को एलडीसीई एवं जीडीसीई के आधार पर सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों पर भरने का आदेश दिया जाए, लोको पायलट व सहायक लोको पायलट की कि बढ़ते यातायात के अनुसार बीओएस को संशोधित करते हुए वृद्धि किया जाए जिससे क्रू को पूर्ण विश्राम मिल सके व बनारस से शुरू होने वाली गाड़ियों का वाराणसी मंडल के क्रू से अंतर मंडली/रेलवे चलाया जाए जिससे क्रू का पूर्ण समायोजन हो सके आदि बहुत सी समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक उदय बोरवणकर से कहा गया।

सराय कला बस स्टैंड पर केन्द्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव का फूंका पुतला

देश का दर्पण दैनिक
न्यूज खैरथल संवाददाता
अमित शर्मा

खैरथल। खैरथल जिला मुख्यालय का नाम परिवर्तन व मुख्यालय बदलने के विरोध में इकतीस गांव की सरदारी सराय कला परगना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में सराय बस स्टैंड पर सांसद व मंत्री भूपेंद्र यादव का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया इस अवसर पर अखिलेश कौशिक ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मुंडावर राम अवतार चौधरी संगठन महामंत्री एवं पूर्व अपर लोक अभियोजक मुंडावर कीमतराय शर्मा, वीरेंद्र मास्टर लक्ष्मी चंद डागुर हनुमान प्रसाद, मलूका कुलदीप चौधरी वीरेंद्र सिंह लक्ष्मी कुलदीप डागर और अनेकों लोगों ने नाराजगी व्यक्त की।

जैसलमेर बस दुखान्तिका में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति खैरथल द्वारा दो मिनट का मौन धारण कर दी श्रद्धांजलि

देश का दर्पण दैनिक
न्यूज खैरथल संवाददाता
अमित शर्मा खैरथल

खैरथल खैरथल जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति द्वारा बुधवार को जैसलमेर बस दुखान्तिका में मारे गए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई इस दौरान सर्वेश गुप्ता गिरीश डाटा दीपक चौधरी पहलाद गुप्ता वीर सिंह ढिल्लन कृष्णा चौधरी समेत अनेक लोग मौजूद रहे

भाजपा जयपुर शहर की ओर से दीपावली से पहले 54 गरीब परिवारों के घर स्वरोजगार के माध्यम से हुए रौशन

जयपुर । जयपुर शहर भाजपा की ओर से दीपावली से पूर्व आयोजित ह्लआत्मनिर्भर भारत एवं संकल्पह्व अभियान के तहत गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार उत्सव मनाया गया। इस मौके पर घुमंतू जाति उत्थान न्यास द्वारा कार्यकुशलता और रुचि के आधार पर चिन्हित विधवा महिलाओं, गरीब और निराश्रित परिवारों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की गई। भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया इस कार्यक्रम के तहत 54 परिवारों को ठेले विभिन्न प्रकार की सामग्री सहित, कबाड़ी के कार्य के लिए 7 ट्रॉली रिक्शा, वजन तोलने की मशीनें, वैल्डिंग

की मशीनें, लोहारी का सामान, सौंदर्य निखार उत्पाद, मूंगफली, गजक के ठेले, किराने का सामान और विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधन प्रदान किऐ । केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे उदाहरण देकर बताया कि भारत अब विश्व स्तरीय तकनीक और उद्योग में आत्मनिर्भर बन रहा है। जयपुर के 5000 युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आज भारत में मोबाइल और अन्य उत्पाद देश में ही विकसित हो रहे हैं। 2014 के बाद निर्णायक नेतृत्व और नीति सुधारो के कारण भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राजस्थान में 85 रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, जयपुर स्टेशन में स्थानीय स्थापत्य, सांस्कृतिक सौंदर्य का समावेश , इसका साक्षात उदाहरण है।

वैष्णव ने सभी लाभार्थियों को माला, दुपट्टा, नारियल भेंट कर उनके रोजगार की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हमें नरेंद्र मोदी के सपने पूरे करने है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आत्मविश्वास और आर्थिक शक्ति को पुनः जागृत किया है । हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शासकीय कार्यों में पूर्ण जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 14 प्रकरणों में कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया है।

4 प्रकरणों में सेवानिवृत अधिकारियों की रोकी पेंशन

अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार, सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 8 प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय किया गया है। साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारियों के चार प्रकरणों में पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में नियम 34-सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है। वहीं, सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में राहत देते हुए परिनिंदा तक सीमित किया गया है।

विद्यालय/ महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी आई

सीवन संवाददाता मसरूर अहमद
सिवान,16अक्टूबर 2025 गुरुवार को आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह - जिला पदाधिकारी, सिवान डॉ आदित्य प्रकाश के निदेर्शानुसार आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 को सिवान जिला के विभिन्न प्रखंडों में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मे डोर टू डोर अभियान, मेहंदी, रंगोली, स्लोगन, साइकिल रैली, मतदाता जागरूकता रैली, महिलाओं द्वारा निकाली गई रैली, मतदाता शपथ ग्रहण आदि आयोजित कर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निदेर्शानुसार स्वीप कैलेंडर के अनुसार सिवान जिले विभिन्न प्रखंडों में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका, सेविका, सहायिका, जीविका दीदी , विकास मित्रों एवं आम नागरिकों द्वारा टोलों में ,घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला मतदाता एवं नये मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्वीप संबंधी गतिविधियों के द्वारा उन्हें मताधिकार के महत्व को साझा किया जा रहा है तथा अपील की जा रही है कि वे अवश्य मतदान करें एवं अपने परिवार को मतदान हेतु प्रेरित करें।

स्वीप का उद्देश्य आम नागरिकों को अपने मताधिकार के लिए जागरूक करना है साथ ही दिनांक 06 नवंबर को होने वाले मतदान में जिले के सभी मतदाता शामिल हों और उत्साह पूर्वक भाग लें। इसे केवल चुनाव नहीं बल्कि महापर्व के रूप में मनाने हेतु भी अपील की गई।

सिवान ने भरी उड़ान
चलो चले करें मतदान। ।
बाद में करना सारे काम
चलो पहले करें मतदान ।।

प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक

जयपुर, 16 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस (10 दिसंबर) का आयोजन राजस्थान की ऐतिहासिक और वैभवशाली धरोहर की थीम पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि देश और विदेश से आने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से भी अवगत कराया जाए। उन्होंने आयोजन की सभी तैयारियां आपसी समन्वय से समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री शर्मा ने आगामी 10 दिसंबर

को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जयपुर में होने वाले इस आयोजन में राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति की झलक भी दिखाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रवासी राजस्थानियों को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू की सफल ग्राउंड ब्रेकिंग की उपलब्धियों से अवगत कराएं। इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार करें।

श्री शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स से आने वाले आगन्तुकों की कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली तथा जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने सेक्टोरल सेशन के सफल आयोजन के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों, पर्यटन केन्द्रों और महत्वपूर्ण स्थलों की भी जानकारी दी जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार का धर्म होता है गरीबों की सेवा,नित्यानंद

पातेपुर श्री राम चंद्र उच्च विद्यालय के खेल के मैदान में महुआ में नामांकन कार्यक्रम के बाद आशीर्वाद सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आदि ने संबोधित किया। मिली जानकारी अनुसार पातेपुर नगर पंचायत के श्री राम चंद्र उच्च विद्यालय के खेल के मैदान में आशीर्वाद सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया। पातेपुर विधायक लखेंद्र पासवान द्वारा महुआ अनुमंडल में नामांकन कार्यक्रम के बाद संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभा को संबोधित किया।इस मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि पातेपुर विधानसभा में इस फिर से कमल खिलाना है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पातेपुर की धरती लालटेन की धरती नहीं रहेगी। सरकार का धर्म है जनकल्याणकारी, गरीबों की सेवा अपनी जनता की सुरक्षा।इस मौके पर निवर्तमान विधायक लखेंद्र पासवान मुखिया दिलीप कुमार, पूर्व मुखिया कपिलेश्वर राय, इंद्रजीत सिंह, मुखिया प्रतिनिधि शम्भु यादव,मुख्य पार्षद सनोज पासवान, जय मूरत राय कॉलेज के प्राचार्य राज किशोर राय, घनेश मिश्रा, चूचू मिश्रा, विनय चौधरी, श्रवण कुमार, ब्रजेश कुशवाहा, समेत सैकडों एन डी ए समर्थक मौजूद थें।

दीपोत्सव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एमआई रोड से किया जयपुर की लाइटिंग का शुभारंभ

जयपुर। पंच दिवसीय दीपोत्सव के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राजधानी की एमआई रोड पर रंग-बिरंगी लाइटिंग का स्विच ऑन कर दीपावली उत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपोत्सव केवल रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और नकारात्मकता पर

सकारात्मकता की विजय का प्रतीक है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि व्यापार मंडल की ओर से वोकल फार लोकर थीम पर सजावट की गई। इस प्रकार के आयोजन ना केवल परंपरा को जीवंत रखते हैं, बल्कि मोदी सरकार के स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में महत्वपूर्ण कदम है। दीपोत्सव जनसहभागिता और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि दीपावली को पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखते हुए हर्षोल्लास से मनाएं और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। उल्लेखनीय है कि एमआई रोड पर की गई सजावट में इस बार "वोकल फॉर लोकल" थीम को प्रमुखता दी गई है। यहां लगभग 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में की गई लाइटिंग पूरी तरह से स्वदेशी उत्पादों से की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों व निमार्ताओं को प्रोत्साहन देना है। इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार व कारोबार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया है। यह दीपोत्सव, न केवल आस्था व आनंद का पर्व है, बल्कि यह आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी एक सार्थक पहल बन चुका है।

इस अवसर पर पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कालीचरण सराफ, बाल मुकुंदाचार्य महाराज, भाजपा प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी, भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, मेयर कुसुम यादव, जयपुर ग्रेटर उपमहापौर पुनीत कर्णावत सहित स्थानीय व्यापारी, गणमान्य नागरिक, पार्षदगण व पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

संयोजक, भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग

देश का दर्पण
जयपुर, शुक्रवार
17.10.2025

मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी, मीडिया कोषांग, पेड न्यूज का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी सिवान डॉ आदित्य प्रकाश के द्वारा किया

सीवन संवाददाता मसरूर अहमद

सिवान,16अक्टूबर 2025 गुरुवार को आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सिवान डॉ आदित्य प्रकाश के द्वारा एमसीएमसी कोषांग, मीडिया कोषांग एवं पेड न्यूज कोषांग का निरीक्षण किया गया।जिला जन सम्पर्क कार्यालय,(सूचना भवन) सिवान में संचालित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) कोषांग, मीडिया कोषांग एवं पेड न्यूज के निरीक्षण के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग सह- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सिवान को दिया गया।

निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में समिति के कार्यों की जानकारी ली गई। जिला पदाधिकारी में स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित किए जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म) का पूर्व प्रमाणन करना, ह्यपेड न्यूजह्न की रोकथाम करना तथा प्रचार में किए गए चुनाव व्यय की सटीक निगरानी सुनिश्चित करना है। जिला पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट किया गया कि आयोग के नियमों के विपरीत किसी भी विज्ञापन का प्रसारण/प्रकाशन प्रतिबंधित रहेगा तथा ऐसे मामलों में समिति त्वरित निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। साथ ही व्यय लेखा संधारण से संबंधित दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा की गई। ताकि अभ्यर्थियों के वास्तविक खर्च का लेखा-जोखा पारदर्शी ढंग से दर्ज किया जा सके।

निरीक्षण के क्रम में नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि चार टीवी मॉनिटर के जरिए 24 घंटे तीन पाली में सभी प्रमुख न्यूज चैनलों के जरिए प्रसारित समाचारों का अनुश्रवण किया जा रहा है। किसी भी तरह के नकारात्मक अथवा भ्रामक समाचार पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।

रेडियो के जरिए एफएम पर प्रसारित हो रहे समाचारों पर भी नजर बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

जिला के सोशल मीडिया पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सोशल मीडिया विशेषज्ञ को प्रतिनियुक्त किया गया है। 24 घंटे जिला में सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित होने वाली सामग्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस संबंध में किसी भी तरह के नकारात्मक समाचार प्रचारित या प्रसारित होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मीडिया कोषांग में प्रमुख हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू अखबारों का नियमित रूप से अवलोकन किया जा रहा है। ताकि पेड न्यूज पर कड़ी नजर बनाई जा सके एवं प्रत्याशियों के द्वारा प्रचारित सामग्री पर भी नजर बनाई जा सके। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के खर्च की विवरणी व्यय कोषांग को प्रतिदिन भेजने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा कोषांग में की गई व्यवस्थाओं से संतोष जाहिर किया गया एवं पूरे निर्वाचन अवधि में सजग एवं सतर्क रहने का निर्देश भी दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभायें तथा आयोग द्वारा निर्धारित सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करायें।

इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के साथ एमसीएमसी कोषांग ,मीडिया कोषांग एवं पेड न्यूज में प्रतिनियुक्त कर्मीगण उपस्थित रहें।

खेत में रखी करीब 8 ट्रॉली कड़वी में लगी आग हुई खाक

(आग किन कारणों से लगी नहीं पता चला)

भरतपुर..रूपवास थाना क्षेत्र के दौरा गांव में गुरुवार दोपहर पशुओं के चारे में अचानक आग लग गई। खेत में रखे करीब 8 ट्रॉली चारे में आग लगी थी। समय रहते दमकल विभाग को सूचना दी गई और 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। दमकलकर्मियों के मुताबिक, दोपहर 2 बजे सूचना मिली और तुरंत गाड़ी मौके पर भेजी गई। आग की लपटें तेज थीं, लेकिन कर्मचारियों ने तेजी से काम करते हुए आग बुझा दी। किसानों ने बताया कि आग लगने का कारण साफ नहीं है। दो किसानों का करीब डेढ़ लाख का चारा जलकर राख हो गया, जबकि बाकी चारा समय रहते हटा लिया गया जिससे बचाव हो सका। गांव के लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

सेवर में मिला नवजात शिशु

देश का दर्पण.. दैनिक अखबार पत्रकार.. राकेश कोठेनिया हलेना सेवर (भरतपुर) नगला झीलरा के जंगल में झाड़ियों मिला नवजात शिशु। जानवरों के चोट के निशान भी बताए जा रहे बालक के शरीर पर। एक ग्रामीण ने राजकीय जनाना हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में बच्चे को कराया भर्ती। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतोली सहित अन्य सदस्यों ने अस्पताल पहुंचकर की जानकारी सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ डॉ हिमांशु गुप्ता की चिकित्सा टीम कर रही बालक की देखभाल। दो तीन पुराना बताया जा रहा है शिशु। अभी शिशु की नहीं हो सकी है पहचान।सेवर थाना क्षेत्र का मामला।

पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया

पातेपुर पूर्व राजद विधायक प्रेमा चौधरी ने महुआ गुरुवार अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर हजारों कार्यकताओं ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद फूल माला से भव्य सम्मानित किया। इस मौके पर पातेपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश राय, मुखिया राम प्रवेश राय, गौतम राम, अभिषेक चौधरी,पूर्व जिला परिषद सीता राम राय, पूर्व प्रमुख राजनरायन राय,मकबूल अंसारी, रीना रागनी , पूर्व मुखिया ललित राय, पूर्व मुखिया बीरेंद्र राय, पूर्व मुखिया अशोक राय , मिथलेश राय, पैक्स अध्यक्ष राज कुमार राय, सावन कुमार शंकर , देव कुमार साहनी, गौतम कुमार,समेत सैकड़ों महागठबंधन के नेता मौजूद थें।

बिहार चुनाव - भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल

पटना 16 अक्टूबर (पीएमए) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। इस सूची में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। इसके अलावा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।

भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भोजपुरी एक्टर के भी नाम हैं, जिनमें पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' शामिल हैं।

भाजपा के स्टार प्रचारकों में स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, सीआर पाटिल, दिलीप कुमार जयसवाल, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, रेनू देवी, प्रेम कुमार, नित्यानन्द राय, राधा मोहन सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति और सतीश चंद्र दुबे शामिल हैं। इसके अलावा ही, राज भूषण चौधरी, अश्विनी कुमार चौबे, रविशंकर प्रसाद, नन्द किशोर यादव, राजीव प्रताप रूडी, संजय जयसवाल, विनोद तावड़े, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप कुमार सिंह, गोपालजी ठाकुर और जनक राम भी बिहार में प्रचार करेंगे।

बता दें कि एनडीए के सीट शेयरिंग के अनुसार, भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें और आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिली हैं। इसके तहत भाजपा ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र 2025 की नहीं, बल्कि 1945 की वास्तविकताओं को दशार्ता है : एस जयशंकर

नई दिल्ली :(पीएमए) भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र 2025 की वास्तविकताओं के बजाय 1945 की दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। एक बार फिर से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन (यूएनटीसीसी 2025) में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि शांति स्थापना के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसके सभ्यतागत लोकाचार में निहित है और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। उन्होंने आगे कहा, "सैन्य योगदानकर्ता देशों के सैन्य नेताओं शांति के निमार्ता, संरक्षक और दूत की इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप एक ऐसी संस्था संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की ताकत को दशार्ते हैं, जो लगभग आठ दशकों से संघर्षग्रस्त दुनिया में आशा की किरण के रूप में उभरी है।"

उन्होंने कहा कि भारत का शांति स्थापना दर्शन इस विचार से प्रेरित है कि वैश्विक सहयोग न्याय और समावेशिता पर आधारित होना चाहिए। जयशंकर ने कहा, "भारत शांति स्थापना को अपने सभ्यतागत मूल्यों से जोड़ता है। हम विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं; यह दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुम्बकम' के शाश्वत सिद्धांत में निहित है। यह केवल सांस्कृतिक ज्ञान ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे विश्वदृष्टिकोण का आधार है।"

उन्होंने आगे कहा, "यही कारण है कि भारत ने सभी समाजों और लोगों के लिए न्याय, सम्मान, अवसर और समृद्धि की निरंतर वकालत की है। यही कारण है कि हम बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में अपना विश्वास रखते हैं।" आधुनिक युग से जुड़ी चुनौतियों को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमारी प्रतिक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रतिस्पर्धी पहलुओं से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे सहयोगों का स्वाभाविक प्रारंभिक बिंदु संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की बैठक के लिए न्यूयॉर्क की अपनी हालिया यात्रा के अनुभव साझा करते हुए, भारत के विदेश मंत्री ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र आज भी 1945 की वास्तविकताओं को दशार्ता है, न कि 2025 की। अस्सी साल किसी भी मानदंड से एक लंबा समय है, और इस अवधि के दौरान, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता वास्तव में चौगुनी हो गई है।"

विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर पिक्चर पोस्ट कार्ड का विमोचन

जयपुर जीपीओ में विश्व खाद्य दिवस के अवसर राजस्थान का देशी पौष्टिक भोजन थीम पर पिक्चर पोस्टर का विमोचन किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान डाक परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (CPMG) महोदय श्रीमान कर्नल सुशील कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल दक्षिण क्षेत्र बी एल सोनल , निदेशक डाक सेवायें (मुख्यालय) (DPS HQ) महोदया अनुब्रता संकरकुमार दास , प्रवर अधीक्षक डाकघर प्रियंका गुप्ता ,सहायक निदेशक प्रवीण सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डाक कर्मचारी उपस्थित रहे ।

कार्यक्रम में राजस्थान का पौष्टिक देशी भोजन थीम पर 5 पिक्चर पोस्ट कार्ड सेट जिसमे केर सांगरी , हल्दी की सब्जी , मंगोड़ी , मेथी दाना , ग्वार फली की सब्जी को शामिल किया गया कार्यक्रम में पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान परिमंडल एवं अन्य उच्च अधिकारीयों द्वारा विमोचन के अवसर पर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि आज के समय में जब फास्ट फूड संस्कृति बढ़ रही है, ऐसे में पारंपरिक भोजन की ओर लौटना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान के स्थानीय खाद्य पदार्थ न केवल पौष्टिक हैं, बल्कि जलवायु अनुकूल और पर्यावरणीय दृष्टि से भी टिकाऊ हैं।

आई लव मोहम्मद कहना चाहते हैं, तो इसे शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से साबित करें

हाल के दिनों में ह्लआई लव मोहम्मदह्व विवाद ने देशभर में बहस और भावनाओं का माहौल बना दिया है। जगह-जगह विरोध, नारेबाजी और सड़क जाम जैसी घटनाएँ देखने को मिलीं। पर इस पूरे शोरगुल में एक अहम सवाल दब गया—क्या पैगम्बर मुहम्मद ने हमें यही सिखाया था ? क्या उन्होंने अपने अनुयायियों को अपमान के जवाब में गुस्से से भर जाने की सीख दी थी ?

मुसलमान होने के नाते, पैगम्बर के प्रति प्रेम हमारी ईमान का हिस्सा है। लेकिन यह प्रेम केवल शब्दों या नारों में नहीं, बल्कि उनके जीवन के आदर्शों को अपनाने में झलकना चाहिए। पैगम्बर का जीवन संयम, करुणा और क्षमा की मिसाल है। उन्होंने अपमान और अन्याय के जवाब में हमेशा सब्र और हिकमत का रास्ता चुना। जब ताइफ के लोगों ने उनका स्वागत पत्थरों से किया, तब भी उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि अल्लाह से दुआ की—ह्लहे अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।ह्व यहाँ तक कि जब फरिश्ता जिब्रील ने उन लोगों पर पहाड़ गिराने की अनुमति माँगी, तो पैगम्बर ने मना करते हुए कहा कि शायद उनकी आने वाली पीढ़ियाँ सत्य को स्वीकार करेंगी। यही था उनका दृष्टिकोण विरोध को अवसर में और नफरत को मुहब्बत में बदल देना।

मक्का में वर्षों तक चले अत्याचारों, अपमान और बहिष्कार के बावजूद उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने समाज को क्रांति और सुधार का पाठ तलवार से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और नैतिकता से पढ़ाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में है। उन्होंने फरमाया कि शक्तिशाली वह नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वह है जो गुस्से में खुद पर काबू रखे।

कुरआन भी यही शिक्षा देता है कि जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं, तो उनसे दूर हो जाओ जब तक कि वे किसी और बात में न लग जाए और एक और स्थान पर स्पष्ट कहा गया कि बुराई का जवाब भलाई से दो। इस्लाम का संदेश साफ है कि सम्मान, दया और संयम। लेकिन आज जब सड़कों पर विरोध के नाम पर हिंसा और अव्यवस्था फैलती है, तो यह सवाल उठता है कि क्या इससे इस्लाम की छवि मजबूत होती है या और कमजोर पड़ती है ? क्या इससे पैगम्बर का सम्मान बढ़ता है या समाज में विभाजन और नफरत गहरी होती है ? हर बार जब हम भावनाओं में बहकर गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अनजाने में उसी धारणा को मजबूत करते हैं जिसे इस्लाम विरोधी दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान असहिष्णु हैं। जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। इस्लाम सब्र, हिकमत और रहमत का धर्म है।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी सिवान के निदेशानुसार मतदान कराने वाले मतदान पदाधिकारी को आज दिनांक 16.10.2025 को दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया

सीवन संवाददाता मसरूर अहमद

सिवानः गुरुवार को नोडल पदाधिकारी (प्रशिक्षण कोषांग) एवं मास्टर प्रशिक्षकों ने मतदान पदाधिकारी को कार्य एवं दायित्व का बोध कराते हुए बताया कि इस चुनाव में 100% मतदान केन्द्र का Web Casting होगा।

पीठासीन पदाधिकारी EVM सेट के साथ (17C) भरकर जमा करेंगे। (17C) उपस्थित मतदान अभिकर्ता को हस्तगत कराते हुए Receiving लेना है। सभी पीठासीन पदाधिकारी को श्ळफ अस्त्रस्त्र Mobile में Downloads करके प्रत्येक दो घंटे पर इसमें रिर्पोट दर्ज करना अनिवार्य है। सभी सेक्टर पदाधिकारी को एश्ट का मॉक ड्रिल के समय कम से कम एक सौ मत देने का निदेश दिया गया एवं मत डालने के पश्चात एश्ट मॉक ड्रिल से संबंधी प्रमाणपत्र भरकर जमा करने का निदेश दिया गया, नोडल पदाधिकारी (प्रशिक्षण कोषांग) के द्वारा सभी मास्टर प्रशिक्षको को निदेश दिया गया कि मतदान पदाधिकारी को मतदान से संबंधित सारी जानकारी देगें।

नोडल मास्टर प्रशिक्षक ने मतदान पदाधिकारी को प्रशिक्षण के दौरान कहा कि तृतीय मतदान पदाधिकारी उव के प्रभारी होंगे, एवं मतदाता से मतदात पर्ची प्राप्त कर तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही की जाँच कर बैलेट बटन को दबाकर मत देने के लिए मतदाता कक्ष में भेजेंगे।

मतदाता पर्ची को सुरक्षित जमा करमें रहेंगे, एवं मतदाता द्वारा मत देने के पश्चात होने वाली बीप ध्वनी का ध्यान रखेंगे। बीप की ध्वनी समाप्त होने के पश्चात तथा मतदान प्रकोष्ठ में गये मतदाता के बाहर निकल जाने के पश्चात ही अगले मतदाता प्रकोष्ठ में जाने हेतु अनुरोध करेंगे। मतदान समाप्ति के उपरांत संग्रहित सभी मतदाता पर्ची पीठासीन पदाधिकारी को हस्तगत कराएगें।

बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ नहीं, तबीयत बिगड़ने से गई श्रद्धालु की जान

मथुराः (पीएमए) उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बीते सोमवार शाम एक दुखद हादसा हुआ। मेरठ निवासी 56 वर्षीय कृपाल सिंह नाम के श्रद्धालु की मंदिर दर्शन के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

क्या हुआ मंदिर में ?

मिली जानकारी के मुताबिक, कृपाल सिंह अपने परिवार के साथ मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र के निलोहा गांव से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए थे। सोमवार को जब वे गेट नंबर 4 से बाहर निकल रहे थे, तभी अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। वहां तैनात सुरक्षा गार्डों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा ?

मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कृपाल सिंह भीड़ के बीच लड़खड़ाते हुए अचानक नीचे गिर जाते हैं। आसपास मौजूद श्रद्धालु और पुलिसकर्मी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं। एंबुलेंस बुलाकर तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पहले से थी सांस की तकलीफ

कृपाल सिंह के परिजनों ने बताया कि उन्हें पहले से ही सांस लेने में तकलीफ रहती थी।

सोमवार को मंदिर में दर्शन के समय भीड़ अधिक थी, जिससे उन्हें घुटन महसूस हुई और इसी कारण उनकी हालत बिगड़ गई। परिवार के सदस्य अवधपाल सिंह ने कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, जैसे-तैसे दर्शन कर लौटे, लेकिन कृपाल जी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो संभल नहीं पाए।

पुलिस का क्या कहना है ?

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि श्रद्धालु की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया क्योंकि परिजन की तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने बताया कि कृपाल सिंह को पहले से सांस की बीमारी थी। पुलिस ने मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और कोई संदिग्ध गतिविधि या कारण नजर नहीं आया है। मंदिर की भीड़भाड़ को हादसे का कारण नहीं माना गया है।

परिजनों को सौंपा गया शव

मृतक का शव कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन और पुलिस ने भीड़ नियंत्रण को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही है।

भारत की तेल खरीद पर ट्रंप के दावों को रूसी राजदूत ने किया खारिज

नई दिल्ली : (पीएमए) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के तेल व्यापार पर दिए अपने बयान से हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने आईएएनएस से बातचीत की। डेनिस अलीपोव ने कहा, "मुझे भारतीय प्रधानमंत्री और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत की जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, वह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय मामला है। हम इस समझ से आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार की नीतियां सबसे पहले भारतीय लोगों के हितों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों को दशार्ती हैं और ये लक्ष्य रूस-भारत संबंधों के विपरीत नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि वास्तव में यह एक तथ्य है कि हम विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार के साथ बहुत करीबी बातचीत कर रहे हैं। हमारे बीच एक विश्वसनीय संवाद है, एक बहुत व्यापक बातचीत है और भारत को रूसी तेल की आपूर्ति के हमारे पास आंकड़े हैं। हमारे बीच निरंतर सहयोग चल रहा है। मुझे लगता है कि हम भारत के साथ इस क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा जारी रखेंगे।

भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर रूसी राजदूत ने कहा, "जहां तक भारत और अमेरिका के संबंधों का सवाल है, हम उन मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यह अमेरिका के साथ भारत का एक द्विपक्षीय संबंध है, और भारत का हमारे साथ एक द्विपक्षीय संबंध है। हम उन्हें स्वतंत्र मानते हैं। हमारा रिश्ता किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा मानना ??है कि हमारी तेल आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है।

उन्होंने कहा कि भारत-रूस के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ रहे हैं। व्यावसायिक-से-व्यावसायिक संपर्क बढ़ रहा है। हम कई बड़ी, छोटी और बड़ी परियोजनाओं, द्विपक्षीय परियोजनाओं पर गहन चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि हम अपने आर्थिक संबंधों के और विस्तार और गहराई की ओर देख रहे हैं। यह हमारा द्विपक्षीय मार्ग है। यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे राष्ट्रों के लाभ के लिए स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहा है और मुझे लगता है कि हमने अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं और हमारे सामने बहुत उज्ज्वल संभावनाएं हैं।

रूसी राजदूत ने जानकारी दी है कि भारत और रूस के बीच कई क्षेत्रों में चर्चा चल रही है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा का इंतजार है।

पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, सीबीआई ने मोहाली दफ़्तर से दबोचा

चंडीगढ़ 16 अक्टूबर (पीएमए) पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) हरचरण सिंह भुल्लर को गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, भुल्लर को मोहाली स्थित उनके कार्यालय से रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जांच एजेंसी की टीम ने उनके कार्यालय, आवास और एक अन्य ठिकाने पर छापेमारी की। छापों के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने बताया कि भुल्लर पर एक स्क्रैप व्यापारी से रिश्वत लेने का आरोप था। व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि डीआईजी लगातार उससे अवैध भुगतान की मांग कर रहे थे। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने ट्रैप ऑपरेशन चलाया और गुरुवार को उन्हें रिश्वत की राशि स्वीकार करते समय गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने मामले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि डीआईजी स्तर का यह अधिकारी पिछले कुछ समय से स्थानीय व्यापारियों और ठेकेदारों से कथित रूप से आर्थिक लाभ उठा रहा था।

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम ने भुल्लर के मोहाली कार्यालय, निजी आवास और एक परिचित के घर पर छापेमारी की। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजात बरामद किए गए।सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि इन दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी और इन्हें सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा।

गिरफ्तारी के बाद भुल्लर को पंचकूला स्थित सीबीआई कार्यालय ले जाया गया, जहां देर शाम तक उनसे पूछताछ की गई। शुक्रवार को उन्हें चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां एजेंसी ने रिमांड की मांग की।सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई अधिकारियों को शक है कि इस प्रकरण में अन्य पुलिस अधिकारी और स्थानीय कारोबारी भी शामिल हो सकते हैं। एजेंसी ने अब इस दिशा में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। हरचरण सिंह भुल्लर 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे पूर्व में पटियाला रेंज में तैनात रह चुके हैं।

उनके पिता मेहल सिंह भुल्लर पंजाब के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी राजनीति और प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं।उनकी गिरफ्तारी को पंजाब पुलिस सेवा में एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे राज्य के वरिष्ठ और प्रभावशाली अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री बैरवा ने आरएएस में चयनित अभ्यर्थियों से मुलाकात कर दी बधाई, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहने की सीख दी

जयपुर, 16 अक्टूबर। सरकारी नौकरी सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है। आम जन बहुत विश्वास से अपने कार्य के लिए सरकारी कार्यालय जाता है। उसे सही दिशा मिल जाए तो उसके परिवार, गांव, क्षेत्र की बड़ी समस्या दूर हो जाती है। आप लोगों ने मेहनत और समर्पण से सफलता अर्जित की है जिसमें कहीं न कहीं आपके परिवार, गुरूजन या किसी अन्य सदाशय व्यक्ति का सहयोग रहा होगा। अपने राजकीय दायित्व से परे भी कमजोर और विकास की दौड़ में पिछड़े कम से कम 1 परिवार का जीवन संवार कर "गिव बैक टू सोसायटी" की भावना को साकार करें। सदैव राष्ट्र सेवा को प्रथम रखें।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा–2023 में चयनित हुए राज्यभर से आए हुए अभ्यर्थियों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने उन्हें यह प्रेरणा दी। इस दौरान दूदू विधानसभा क्षेत्र से भी सफल अभ्यर्थी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने चयनित हुए सभी अभ्यर्थियों से आत्मीय भेंट कर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की। डॉ. बैरवा ने बताया कि यह सफलता आप सभी के कठिन परिश्रम, निष्ठा और समर्पण का परिणाम है। विश्वास है कि आप अपनी कर्मठता और ईमानदारी से प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाएँगे। उन्होंने उपस्थित अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना भी की ।

शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, 2200 किलो बेसन को जब्त किया, 6 खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया) 16 अक्टूबर। दीपावली के त्यौहार पर आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभमंगला और जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए एक मावा विक्रेता से मावा का नमूना लिया। इसके पश्चात श्री कैला देवी फूड प्रोडक्टस इंडस्ट्रियल एरिया में एक बेसन का नमूना लेकर 700 किलोग्राम बेसन को सीज किया। इसी क्रम में मैसर्स बाबूलाल रामदयाल रीको इंडस्ट्रियल एरिया से एक बेसन का नमूना लेकर 1500 किलोग्राम बेसन को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में अग्रिम कार्यवाही हेतु रखवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोनो फर्मो को धारा 32 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जा रहा है। जिले भर में विभाग द्वारा मुस्तैदी के साथ मिलावट खोरों के विरुद्ध अभियान दीपावली तक लगातार संचालित किया जाएगा।

जीके सिटी सेवा समिति के अध्यक्ष बने मधुसूदन दुबे

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया) 16 अक्टूबर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर जीटी रोड पर पप्पू जाट ढाबा के पास स्थित जीके सिटी कॉलोनी में जीके सिटी सेवा समिति के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में समाजसेवी मधुसूदन दुबे को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। जीके सिटी स्थित श्री हीरामणि रघुनाथ मंदिर परिसर में संपन्न हुए चुनाव के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष मधुसूदन दुबे जी ने उपस्थित निवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जीके सिटी के हित में जो भी संभव होगा, वह तन-मन-धन से नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगें। सभी के सहयोग और समन्वय से जी.के. सिटी में विकास और सद्भावना को गति प्रदान करेंगें। कार्यकारिणी में प्रताप सिंह राना को अध्यक्ष की अनुमति से उपाध्यक्ष चुना गया। दुबे ने बताया कि कार्यकारिणी का शीघ्र ही विस्तार किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों और समाज के लोगों का ध्यान रखा जाएगा। बैठक के उपरांत कॉलोनीवासियों ने दुबे व राना को हार्दिक बधाइयाँ दीं और आशा व्यक्त की कि इनके नेतृत्व में कॉलोनी के विकास को नई गति मिलेगी।

परिवहन विभाग ने स्लीपर बसों की सख्ती से जांच कर कर की कठोर कार्यवाही,

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर(धर्मेन्द्र बिधौलिया) 16 अक्टूबर। **शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं स**ड़क सुरक्षा विभाग जयपुर के निदेर्शानुसार जिले में पंजीकृत एवं संचालित होने वाली समस्त स्लीपर बसों की सख्ती से जांच किए जाने के आदेशों की पालना में विभाग द्वारा कल से ही जिले में होकर गुजर रही स्लीपर बसों की नियमानुसार जांच शुरू कर दी गई है जिसमें ए आई एस 52/119 मानकों के अनुरूप बसों की बॉडी की बनावट ना होने, बसों में इमरजेंसी गेट, अग्निशमन यंत्र स्लीपर एवं सीटिंग कैपेसिटी नियमानुसार नहीं होने एवं परमिट के उल्लंघन में संचालित ऐसी सभी बसों का चालान बनाकर उनको सीज किया जा रहा है।

जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि कार्यालय के उड़नदस्ते द्वारा ऐसी डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सीज किया गया है,साथ ही यह कार्रवाई निरंतर रूप से आगे भी जारी रहेगी ।एसी बसें जो जिनकी बॉडी नियमानुसार नहीं पाई गई है, उनकी आरसी निलंबन की तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई है। समस्त बस ऑपरेटर एवं वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि बसों मैं इमरजेंसी गेट,अग्निशमन यंत्र, स्लीपर एवं सीटिंग कैपेसिटी नियम अनुरूप कर नियमानुसार ही संचालित किया जावे।

जिला फाजिल्का में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

फाजिल्का, 16 अक्टूबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा) माननीय न्यायमूर्ति श्री अश्विनी कुमार मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) और श्रीमती नवजोत कौर, माननीय सदस्य सचिव, पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के दिशा-निदेर्शों के अंतर्गत, श्री अवतार सिंह, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का के नेतृत्व में और श्रीमती रुचि स्वप्न शर्मा, माननीय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फाजिल्का की देखरेख में, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13.12.2025 को फाजिल्का में आयोजित की जा रही है।

इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को त्वरित, सस्ती और प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना और सलाह के अनुसार मामलों का तुरंत समाधान करना है। इस दौरान सिविल, क्रिमिनल, लेबर और कई अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के दौरान, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मुफ्त कानूनी सलाह, हेल्प डेस्क, कानूनी सहायता शिविर और लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करेगा।

मैडम रुचि स्वप्न शर्मा, माननीय सचिव, डीएलएसए, फाजिल्का ने कहा कि इस लोक अदालत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों की पूरी सहायता मिले और कोई भी कानूनी सहायता से वंचित न रहे। इस दौरान प्राप्त जानकारी को संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके।

किसी भी अन्य कानूनी जानकारी या सलाह के लिए टोल-फ्री नंबर 15100 या डीएलएसए फाजिल्का कार्यालय नंबर 01638-261500 पर संपर्क किया जा सकता है।

विधायक सेखों ने बाढ़ पीड़ितों को 36 लाख 86 हजार रुपये के मुआवजे के स्वीकृति पत्र वितरित

सादिक (फरीदकोट), 16 अक्टूबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा) मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की अनूठी पहल के तहत, पंजाब सरकार ने दिवाली से पहले बाढ़ पीड़ितों/प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को राहत मुआवजा प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। आज मिशन पुनर्वास के अंतर्गत, विधायक स. गुरदित्त सिंह सेखों द्वारा फरीदकोट ज़िले के 10 गाँवों के 150 बाढ़ प्रभावित परिवारों को कुल 36 लाख 86 हजार रुपये की राशि उनके निर्वाचन क्षेत्र के गाँव शेर सिंह वाला में आयोजित एक समारोह में वितरित की गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में स. गुरदित्त सिंह सेखों ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की सरकार द्वारा लोगों से किया गया वादा पूरा किया गया है। दिवाली से पहले यह राहत प्रदान करके सरकार ने साबित कर दिया है कि यह आम जनता की सरकार है जो हर संकट में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि आज मकानों के नुकसान के लिए 15 लाख 86 हजार रुपये और फसलों के नुकसान के लिए 21 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा दिया जा रहा है और मकानों के नुकसान का मुआवजा भी तुरंत दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिया गया मुआवजा देश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, गिरदावरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की गई है ताकि किसी भी किसान या परिवार के साथ अन्याय न हो।सेखों ने बताया कि बाढ़ प्रभावित किसानों को गेहूँ की बुआई के लिए मुफ़्त बीज दिए जा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित गाँवों में मुफ़्त स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं और पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि "जिसका खेत, उसकी रात" नीति के तहत, पंजाब सरकार किसानों को बिना किसी परमिट के अपने खेतों में जमा रेत या गाद को हटाने या बेचने की आजादी दे रही है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है।

जिला कलक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने किया राजकीय अस्पतालों का निरीक्षण

जयपुर, 15 अक्टूबर। **जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार** सोनी के निदेर्शों की अनुपालना में बुधवार को जिले के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तहसीलदारों ने अपने क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा नायब तहसीलदारों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अग्निशमन प्रबंधन, दवाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता, साफ-सफाई, बिजली व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों का विस्तृत जायजा लिया। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने स्वयं राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। उन्होंने अस्पताल में आवश्यक सुधार हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल, डिप्टी सीएमएचओ (हेल्थ) डॉ. सुरेन्द्र कुमार गोयल तथा डिप्टी कंट्रोलर श्री राजाराम उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कलक्टर ने प्रवेश द्वार, आपातकालीन ईकाई, कॉरिडोर सहित 29 स्थानों पर स्थापित अग्निशमन यंत्रों का निरीक्षण किया और पानी के प्रेशर व कार्यक्षमता की जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी आकस्मिक आगजनी की स्थिति में निपटने हेतु अग्निशमन इकाई पर 247 कर्मचारी तैनात रहें और समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाए।

अतिरिक्त उपायुक्त के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

फरीदकोट, 16 अक्टूबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा) जिले में सड़क सुरक्षा नियमों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से अतिरिक्त उपायुक्त महोदया हरजोत कौर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि आम जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करने के साथ-साथ उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अनाधिकृत पार्किंग, तेज गति और ओवरलोड वाहनों के चालान काटे जाएं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर विशेष दंड लगाया जाए और उनके अभिभावकों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

त्यौहार के दिनों में चाक चौबंद रखें सुरक्षा, सफाई, बिजली और पानी की आपूर्ति- विधानसभा अध्यक्ष,

जयपुर, 15 अक्टूबर। **वि**धानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि शहर मे क्षतिग्रस्त हुई समस्त सड़कों को दीपावली से पूर्व मरम्मत एवं नवीनीकरण करवाएं। सुरक्षा, पानी व बिजली की आपूर्ति तथा सफाई व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखें।

विधानसभा अध्यक्ष ने जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु, नगर निगम, एडीए तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ शहर के हित से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की। श्री देवनानी ने निर्देश दिए कि अजमेर शहर में क्षतिग्रस्त हुई समस्त सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण दीपावली से पूर्व कर लिया जाए। दीपावली बड़ा त्यौहार है, ?से में शहर के लोगों को समय रहते राहत प्रदान की जाए। इसके लिए नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर काम किया जाए। श्री देवनानी ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं पर तेजी से अमल किया जाए ताकि समय से काम पूरा हो सके।

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी जिलाधिकारी एंव एसपी को दीपावली एवं छठ को बैठक करने के लिए दिया आवश्यक दिशा निर्देश - मुख्य सचिव

देश का दर्पण न्यूज संवाददाता रमेश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट बिहार वैशाली से

मुख्य सचिव बिहार के द्वारा सभी जिलों के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जिलों में छठ व दीपावली के आयोजनों के संबंध में बैठक आहूत की गई।

मुख्य सचिव के द्वारा छठ पर्व पर व दीपावली को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को शांति समिति की बैठक कर सांप्रदायिक सद्भाव के दृष्टिकोण से पैनी नजर रखने, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी ,गश्ती दल के संबंध में, यातायात संधारण ,मद्य निषेध जांच संबंधी, एनडीआरएफ टीम की प्रतिनियुक्ति ,अग्निशमन, मेडिकल टीम ,पटाखा दुकानों के लाइसेंस, पटाखा स्टोरेज आदि अन्य पक्षों पर आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया है।इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण के साथ शांतिपूर्ण त्योहारों का आयोजन करने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त बैठक में सभी जिला के जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ कर उपस्थित थे।

ब्यूटी आइकॉन वैशाली भाऊरजार को मिला 'अखंड भारत गौरव अवार्ड'

मुंबई की चर्चित प्रकाशन समूह 'मुंबई ग्लोबल' द्वारा पिछले दिनों अंधेरी वेस्ट स्थित एलिट बैंक्वेट हॉल में आयोजित अखंड भारत अवार्ड 2025 समारोह में ब्यूटी आइकन मेगा मॉडल वैशाली भाऊरजार को सुप्रसिद्ध फिल्म निमार्ता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (मुंबई) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी, सिंगर दीपा नारायण और बॉलीवुड आइकॉन जे. ब्रैंडन हिल की उपस्थिति में अवार्ड दे कर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व ब्यूटी आइकन वैशाली भाऊरजार को महात्मा गांधी रत्न अवॉर्ड 2025 समारोह में 'मिस इंडिया विनर' का खिताब मिल चुका है और बॉलीवुड लीजेंड फिल्म फेस्टिवल 2025 के दौरान भी सम्मानित की जा चुकी हैं। लगातार मिल रहे ये राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार इस बात को दशार्ते हैं कि वैशाली आज न केवल फैशन इंडस्ट्री की सशक्त आवाज हैं, बल्कि देश की प्रेरणास्रोत व्यक्तित्वों में से एक बन चुकी हैं। फैशन और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें बॉलीवुड आइकॉनिक अवॉर्ड 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अवॉर्ड उन्हें निमार्ता, निर्देशक और अभिनेता डॉ. धीरज कुमार के हाथों बेस्ट सुपर मॉडल के रूप में प्रदान किया गया था। यह उनके करियर का एक और सुनहरा अध्याय बना। वैशाली आज कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई है। वैशाली का मॉडलिंग करियर जितना ग्लैमरस है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई की मूल निवासी वैशाली भाऊरजार की मॉडल बनने की कहानी काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। वैशाली प्रारंभ में एयर होस्टेस बनना चाहती थी और वह बनी भी। किंगफिशर एयरलाइंस के साथ उन्होंने एक्स कैबिन क्रू(एयरहोस्टेस) के रूप में काम भी किया मगर उनकी किस्मत ने उन्हें मॉडलिंग की दुनिया मे ला दिया।अपनी मेहनत, आत्मबल और कला कौशल के बल पर वैशाली भाऊरजार ने न केवल आला मुकाम हासिल किया है, बल्कि एक सफल मॉडल के रूप में युवाओं की प्रेरणा श्रोत बन चुकी हैं।

प्रस्तुति : काली दास पाण्डेय

डॉ. आशा बिधौलिया को जिला स्तरीय धन्वन्तरि समारोह में किया गया सम्मानित

देश का दर्पण न्यूज, जयपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया) 16 अक्टूबर। **डा.आशा बिधौलिया** (आयुर्वेद चिकित्साधिकारी,जामडोली)को जयपुर के आयुष भवन के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय धन्वन्तरि जयन्ती सम्मान समारोह में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का आरंभ भगवान धन्वन्तरि के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।

समारोह में विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी,कार्मिकों को सम्मानित किया गया।

इस मौके पर आयुर्वेद विभाग के जयपुर जिले के ब क्षेत्र के उपनिदेशक डॉ .पीएल मीना ने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले चिकित्सकों की और भी महती जिम्मेदारी से विभागीय गतिविधियों मे,नवाचारों में आयुर्वेद के लिए उत्कृष्ट कार्य करने की जिम्मेदारी बढ जायेगी।

यह सम्मान के साथ और भी समर्पित होकर कार्य करने का भाव जगाने का एक माध्यम है,ताकि कार्मिक उत्साहित होकर सदैव कार्य करता रहे। इस मौके पर आयुर्वेद विभाग के अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत मे सहायक आयुर्वेद विभाग जयपुर "ब " क्षेत्र के सहायक उपनिदेशक डॉ. अंशुमान चतुर्वेदी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समारोह का समापन किया।

घर पर ही कैसे पहचानें की गट हेल्थ सही है या नहीं एक्सपर्ट ने बताए आसान तरीके

जब हमारा पेट सही होता है, तो ऐसे में कई बीमारियों से बचाव करने में मदद मिलती है. ऐसे में गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए लोग कई तरीके बताते हैं. लेकिन किसी व्यक्ति को यह किस तरह से पता लग सकता है उनका गट हेल्थ सही है या नहीं. आइए जानते हैं इसके बारे में एक्सपर्ट से

सेहत से जुड़ी कई परेशानियों की वजह हमारा खराब डाइजेशन हो सकता है. जब पेट खराब होता हैं, तो ऐसे में स्किन से जुड़ी समस्याएं और इम्यूनिटी कमजोर होने जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा इसका प्रभाव मूड पर भी पड़ता है. इसलिए गट का बेहतर होना बहुत जरूरी है. गट हेल्थ का मतलब पाचन तंत्र का वह हिस्सा है जो मुंह से लेकर कोलन यानी की बड़ी आंत तक फैला होता है. इसे ठीक रखना बहुत जरूरी है, जिससे सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से बचाव किया जा सकता है. ऐसे में आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए.रोजाना खराब खानपान और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ आदतें गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं जैसे कि ज्यादा कैफीन, शराब और धूम्रपान का सेवन. नींद पूरी न करना, शरीर को एक्टिव न रखना, सही मात्रा में पानी न पीना और ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी गट हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में गट हेल्थ बिगड़ने पर शरीर में ये संकेत नजर आ सकते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर सचिन एच जे ने बताया कि अगर आपका पाचन तंत्र सही से काम कर रहा है तो शरीर में एनर्जी बनी रहती है, स्किन साफ दिखती है, मूड अच्छा रहता है और नींद भी सुकूनभरी आती है. लेकिन आपकी गट हेल्थ बिगड़ रही है या नहीं इस बात का अंदाजा आप इन लक्षणों से लगा सकते हैं. अगर रोजाना बिना किसी तकलीफ के एक या दो बार नॉर्मली पेट साफ हो रहा है, पेट में गैस या भारीपन न होना, खाना खाने के बाद फूला हुआ महसूस न हो और भूख सामान्य लग रही है, तो समझिए आपकी गट हेल्थ ठीक है.

दिखाई देते हैं ये संकेत

वहीं अगर बार-बार पेट फूलना, कब्ज, पेट साफ न होना, मुंह में छाले या बार-बार थकान महसूस होना ये गट हेल्थ खराब होने के लक्षण हो सकते हैं. इनसे पता चलता है का गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ा हुआ है. रीजेंसी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट ड्ड गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने बताया कि ऐसी स्थिति में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और देर रात में खाना अवॉइड करें. इसके अलावा दही, छाछ, फल, हरी सब्जियां और फाइबर से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें. सही खानपान, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद और स्ट्रेस को मैनेज करने से गट हेल्थ को नेचुरली सही बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

फाइबर से भरपूर फूड्स

गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. यह कब्ज की समस्या को कम करने और आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के लिए पोषण देता है. कई फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और कई चीजें फाइबर का अच्छा सोर्स होती है. जिसे आप बैलेंस तरीके से डाइट में शामिल कर सकते हैं

अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं

बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना मेंटल हेल्थ के साथ ही हमारी ओवर ऑल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है, जिसमें गट हेल्थ भी शामिल है. क्योंकि स्ट्रेस में शरीर कुछ ऐसे हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जिसके ज्यादा होने पर शरीर पर प्रभाव पड़ता है जिससे गट हेल्थ भी बिगड़ सकती है.

यह महंगाई नहीं, नग्न बाजारवाद का बेशर्म परीक्षण है!

जब आपूर्ति कम होती है तो बाजार में चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं और उनकी कालाबाजारी होती है। अभी न तो जमाखोरी हो रही है, न ही कालाबाजारी। हो रही है तो सिफ़ 'और सिफ़ 'बेहिसाब-बेलगाम मुनाफाखोरी। इसे नग्न बाजारवाद का बेशर्म परीक्षण भी कह सकते हैं। जाहिर है कि सरकार या सरकारों ने अपने आपको जनता से काट लिया है। यह हमारे लोकतंत्र का बिल्कुल नया चेहरा है- घोर जनद्रोही और शुद्ध बाजारपरस्त।

इस समय राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आ रही तमाम दारुण खबरों के बीच आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा निराश-हताश करने और डराने वाली खबर यह है कि उसे महंगाई से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं। बहुत हुई महंगाई की मार... का नारा लगाकर 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी तो अब कभी भूल से भी महंगाई का नाम नहीं लेती। दो महीने पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं जल्दी ही एक बड़ा फैसला लेने जा रहा हूं, जो आपको डबल दिवाली का अहसास कराएगा। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में सुधार करने की बात करते हुए कहा था कि लोगों को दिवाली का तोहफा मिलेगा और उनका जीवन आसान होगा। फिर पिछले महीने यानी सितंबर की 21 तारीख को राष्ट्र के नाम संदेश में उन्होंने जीएसटी की दरों में कटौती का ऐलान करते हुए दावा किया कि इससे आम लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित बचत होगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि जीएसटी की दरों में सुधार से रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें कर मुक्त और कई चीजें सिर्फ पांच फीसदी टैक्स के दायरे में आ गई हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी इस घोषणा को जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया।प्रधानमंत्री की इस घोषणा का मीडिया ने जोर-शोर से प्रचार किया। खुद सरकार ने भी मोदी को गरीबों का मसीहा बताते हुए इसके प्रचार-प्रसार पर अरबों रुपये फूंक डाले। जबकि हकीकत यह है कि जीएसटी की दरों में कटौती का यह फैसला जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिया गया था। गौरतलब है कि देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। इसलिए जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला अकेले प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति से लिया गया था। ऐलान पीएम ने किया था। अगर सभी राज्य सहमत नहीं होते तो यह फैसला नहीं हो सकता था।बहरहाल गाजे-बाजे के साथ हुई प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद बाजार में रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं मसलन अनाज, दाल-दलहन, आटा, चीनी, मसाले, सब्जी, फल, दूध, खाद्य तेल, घी, दवाई, साबुन, कपड़ा, चप्पल-जूते आदि की कीमतों में रत्ती भर की कमी नहीं आई है।

हां, कुछ चीजों के दामों में पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ोतरी जरूर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके दामों में निरंतर कमी आ रही है।ऐसा नहीं कि महंगाई का कहर हाल के वर्षों में कोई पहली बार टूटा हो। महंगाई पहले भी होती रही है। जरूरी चीजों के दाम पहले भी अचानक बढ़ते रहे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद फिर नीचे भी आए हैं परन्तु इस समय तो मानो बाजार में आग लगी हुई है। वस्तुओं की लागत और उनके बाजार भाव में कोई संगति नहीं रह गई है। इस मामले में आम आदमी लाचार और असहाय होते हुए जिस सरकार से आस लगाए हुए है कि वह कुछ करेगी, वह सरकार सिर्फ निर्गुण विकास, स्वदेशी और राष्ट्रवाद का बेसुरा राग अलापते हुए जनता को आत्मनिर्भर बनने की नसीहत दे रही है।कीमतों की इस दोहरी मार ने आम आदमी के भोजन के इंतज़ाम को इकहरा कर दिया है। इस सिलसिले में सरकार की ओर से कभी-कभार दी जाने वाली सफाई भी कतई विश्वसनीय नहीं है। मानसून का कमज़ोर रहना या पर्याप्त बारिश नहीं होना, ऐसा कारण नहीं है कि इनका असर सभी चीजों पर एक साथ पड़े। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कीमतें इतनी ज्यादा होने के बावजूद बाजार में किसी भी आवश्यक वस्तु का अकाल-अभाव दिखाई नहीं पड़ता। जब आपूर्ति कम होती है तो बाजार में चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं और उनकी कालाबाजारी होती है। अभी न तो जमाखोरी हो रही है, न ही कालाबाजारी। हो रही है तो सिफ़ 'और सिफ़ 'बेहिसाब-बेलगाम मुनाफाखोरी। इसे नग्न बाजारवाद का बेशर्म परीक्षण भी कह सकते हैं। जाहिर है कि सरकार या सरकारों ने अपने आपको जनता से काट लिया है। यह हमारे लोकतंत्र का बिल्कुल नया चेहरा है- घोर जनद्रोही और शुद्ध बाजारपरस्त।

तीन दशक पहले तक जब किसी चीज के दाम असामान्य रूप से बढ़ते थे तो सरकारें कुछ तो हस्तक्षेप करती थीं। यह अलग बात है कि इस हस्तक्षेप का कोई खास असर नहीं होता था, क्योंकि उस मूल्य वृद्धि की वजह वाकई उस चीज की दुर्लभता या अपर्याप्त आपूर्ति होती थी। यह स्थिति पैदा होती थी उस वस्तु के कम उत्पादन की वजह से। अब तो सरकारों ने औपचारिकता या दिखावे का हस्तक्षेप भी बंद कर दिया है। वे बिल्कुल बेफ़िक्र हैं- महंगाई का कहर झेल रही जनता को लेकर भी और जनता को लूट रही बाजार की ताकतों को लेकर भी।कुछ साल पहले तक महंगाई पर लगाम लगाने के मक़सद से रिज़र्व बैंक भी हरक़त में आता था और अपने स्तर पर कुछ कदम उठाता था, लेकिन अब महंगाई उसकी चिंता के दायरे में नहीं आती। उसकी स्वायत्ता का अब अपहरण हो चुका है। अब उसका पूरा ध्यान सरकार के दुलारे शेयर बाजार को तंदुरुस्त बनाए रखने और सरकार की गड़बड़ियों को छुपाने में लगा रहता है।

महंगाई को लेकर सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि समूची राजनीति उदासीन बनी हुई है। पहले जब महंगाई बढ़ती थी तो उस पर संसद में चर्चा होती थी। विपक्ष सरकार को सवालों के कठघरे में खड़ा करता था। सरकार भी महंगाई को लेकर चिंता जताती थी। वह महंगाई के लिए जिम्मेदार बाजार के बड़े खिलाड़ियों को डराने या उन्हें निरुत्साहित करने के लिए कठोर कदम भले ही न उठाती हो, पर सख्त बयान तो देती ही थी। अब तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के दस वर्ष के कार्यकाल में 16 मर्तबा संसद में महंगाई के सवाल पर बहस हुई। उससे पहले एनडीए सरकार के छह वर्ष के कार्यकाल में भी 8 मर्तबा इस सवाल पर संसद में लम्बी बहसें हुई थीं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल यानी 16वीं लोकसभा में भी तीन बार संसद में महंगाई पर चर्चा हुई, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल यानी 17वीं लोकसभा के किसी भी सत्र में महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हुई। मौजूदा यानी 18वीं लोकसभा के भी अब तक चार सत्र बीत चुके हैं पर महंगाई का ज़िक्र तक नहीं हुआ है। विपक्ष की ओर से यह मुद्दा उठाने की कोशिश भी की गई तो उसे या तो सत्तापक्ष की नारेबाजी और शोर-गुल में दबा दिया गया या फिर स्पीकर और सभापति ने मुद्दे को उठाने से ही रोक दिया।पाकिस्तान में टमाटर और प्याज के दाम बढ़ने को लेकर कई-कई दिनों तक शोर मचाने वाला भारत का टेलीविज़न मीडिया भी अपने देश की महंगाई का कभी भूले से भी ज़िक्र नहीं करता। याद नहीं आता कि पिछले दस वर्षों में किसी टीवी चैनल ने महंगाई के मुद्दे पर कोई बहस आयोजित की हो। किसी अन्य विषय पर बहस के दौरान विपक्षी दल का कोई प्रवक्ता अगर महंगाई का सवाल छेड़ भी देता है तो चैनल के एंकर की ओर से उसे यह कहते हुए झिड़क दिया जाता है कि वह बहस को मुद्दे से भटकाने का प्रयास न करे। इसी वजह से मुनाफाखोरों, जमाखोरों और कालाबाजारियों को मीडिया की ओर से भी अभयदान मिला हुआ है।

अगर बढ़ी हुई कीमतों का कुछ हिस्सा उत्पादकों तक पहुंच रहा होता या अनाज और सब्ज़ियां उगाने वाले किसान मालामाल हो रहे होते, तब भी कोई बात थी। ऐसा भी नहीं हो रहा है। इस अस्वाभाविक महंगाई का लाभ तो बिचौलिए और मुनाफाखोर बड़े व्यापारी उठा रहे हैं। वैसे मीडिया की सर्वव्यापकता और सक्रियता के दौर में किसी भी सरकार के लिए निर्धारित कीमतों पर चीजें बिकवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा करने का नकारात्मक नतीजा यह हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुएं बाजार से गायब ही हो जाएं। बाजार बनाम सरकार का असली मोर्चा यही होगा। इस मोर्चे पर सरकार को बिचौलियों, जमाखोरों और सट्टेबाजों के खिलाफ सख्ती से पेश आना होगा, क्योंकि चीजों का बनावटी अभाव पैदा कर उनके दामों में मनमानी बढ़ोतरी ये लोग ही करते हैं। सरकार में अगर थोड़ी भी हिम्मत और ईमानदारी हो तो वह बाजार को बेलगाम होने से रोक सकती है।

संपादकीय

बीमार भविष्य की नींव

यह आंकड़ा हमारे शिक्षा तंत्र की विफलता को दर्शाता है कि एक लाख से अधिक स्कूलों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। एक स्कूल की सारी कक्षाओं को एक शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा? छात्र-छात्राएं कैसी और कितनी शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। शिक्षा मंत्रालय के हालिया आंकड़े बताते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में एक लाख चार हजार स्कूल ऐसे थे, जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन स्कूलों में करीब पौने चौंतीस लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है। एक तो हमारे देश में शिक्षा का बजट पहले ही बहुत कम है, फिर उस धन का सही उपयोग नहीं हो पाता। इसमें दो राय नहीं कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के गिरते स्तर के मूल में हमारे नीति-नियंताओं की अनदेखी ही प्रमुख कारक है। आखिर हम अपने नौनिहालों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आखिर उनके बेहतर भविष्य की हम कैसे उम्मीद करें? जाहिर बात है कि एक शिक्षक सामाजिक विषय, भाषा, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित में माहिर नहीं हो सकता। एक शिक्षक छात्रों की हाजिरी दर्ज करेगा या पढ़ाई कराएगा? शिक्षा का मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उन्हें पढ़ाई के साथ पाठ्यसहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन जब स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ही नहीं होंगे तो किताबी पढ़ाई कैसी होगी, अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं होती। बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह हो, उसके लिए खेल, पीटी और योग जैसी कक्षाओं की सख्त जरूरत होती है। लेकिन जब शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो शिक्षा के साथ चलने वाली गतिविधियों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निस्संदेह, हम छात्रों के बीमार भविष्य की बुनियाद ही रख रहे हैं।सही मायनों में स्कूलों का शिक्षकों की कमी से जूझना शिक्षा विभाग की नाकामी को ही दर्शाता है। यह हमारे सत्ताधीशों की संवेदनहीनता का भी पर्याय है। शिक्षकों की नियुक्ति में जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले विभिन्न राज्यों में सामने आए हैं, उससे शिक्षा विभाग की प्रदूषित कार्य संस्कृति का बोध होता है। आखिर क्या वजह है कि देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। यह स्थिति हमारे तंत्र की विफलता को ही उजागर करती है। एक समस्या यह भी है कि शिक्षक जटिल भौगोलिक स्थितियों वाले स्कूलों में काम करने से कतराते हैं। यदि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो भी जाती है तो वे दुर्गम से सुगम स्कूलों में अपना तबादला ज्वाइन करने के तुरंत बाद करवा लेते हैं। जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर विभागीय लेन-देन की भी शिकायत होती रहती है। यही वजह है कि शहरों व आसपास के इलाकों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती जरूरत से ज्यादा भी देखी जाती है। कैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सड़कों पर बेरोजगारों की लाइन लगी हैं और स्कूलों में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं। बताया जाता है कि माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों में करीब साढ़े आठ लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बावजूद कि हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। कहने को तो हमारे गाल बजाते नेता भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहते इतराते हैं, लेकिन इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि कुंठित होती युवा पीढ़ी के लिये उन्होंने क्या खास किया है? नौकरियों की भर्ती निकलती नहीं है। निकलती है तो पेपर आउट होने की खबरें आती हैं। सालों-साल उनके परिणाम नहीं निकलते। यदि परिणाम निकले भी तो फिर धांधली के आरोप लगने लग जाते हैं। फिर मामला वर्षों तक अदालतों में डोलता रहता है। विडंबना यह भी है कि आज सरकारी स्कूलों में गरीब व कमजोर वर्गों के बच्चे ज्यादा भर्ती होते हैं, इसलिए इन स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यदि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के बच्चों के लिये इन स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो स्थिति बदल जाएगी।

घुसपैठियों के खतरे का सच

ाजपा के सर्वोच्च रणनीतिकार माने जाने वाले, अमित शाह ऐलान कर चुके थे कि उनका गठजोड़ बिहार का चुनाव और उससे अगले चरण में कम से कम असम तथा प. बंगाल का चुनाव भी, किस मुद्दे के आसरे लड़ने जा रहा है

यहां तक तो हिंदुओं के लिए बहुत विचलित होने का कारण नहीं बनता । बेशक, देश की कुल आबादी में हिंदुओं का अनुपात घटा है और सलमानों का अनुपात बढ़ा है, लेकिन दोनों की जनसंख्याओं में अंतर तना बड़ा है कि ये आंकड़े शायद ही खास चिंता पैदा करेंगे। आखिरकार, ाठ साल में आबादी में मुसलमानों का अनुपात कुल 4.4 फीसद बढ़ा और हिंदुओं का अनुपात इससे कुछ कम ही घटा है।

भाजपा के सर्वोच्च रणनीतिकार माने जाने वाले, अमित शाह ऐलान र चुके थे कि उनका गठजोड़ बिहार का चुनाव और उससे अगले चरण कम से कम असम तथा प. बंगाल का चुनाव भी, किस मुद्दे के आसरे ाड़ने जा रहा है। यह मुद्दा है-घुसपैठियों का खतरा। दैनिक जागरण के एक ायोजन में अपने सार्वजनिक व्याख्यान में अमित शाह ने यह ऐलान कया। और इसी व्याख्यान में अमित शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सपैठियों से उनका आशय, पड़ोसी देशों से आए मुसलमान प्रवासियों से है, जो आर्थिक कारणों से आते हैं। बंगलादेश, पाकिस्तान, फगानिस्तान आदि, पड़ोसी देशों में कथित रूप से धार्मिक-उत्पीड़न के ारण आने वाले–जाहिर है कि हिंदू–तो घुसपैठिये नहीं प्रवासी !बहरहाल अमित शाह सिर्फ पड़ोसी देशों से आए प्रवासियों को इस तरह ंदू और मुसलमान में विभाजित करने और प्रवासी मुसलमानों को खतरा ौर प्रवासी हिंदुओं को अपना बताने पर ही नहीं रुके। उन्होंने इस खतरे ो बेहिसाब बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का हथकंडा आजमाया, ताकि चुनाव चार के लिए हिंदू खतरे में हैं का जोर-शोर से ढोल पीटा जा सके। यह सरी बात है कि भाजपा के चाणक्य ने यह ढोल कुछ ऐसे अनाड़ीपन से ौर इतने जोर से पीटा कि ढोल ही फट गया। और इस विशाल देश के हमंत्री को, ट्वीट को डिलीट करना पड़ा और बाद में एक संशोधित ट्वीट जारी करना पड़ा, जिसमें से असली पंच लाइन ही गायब हो चुकी थी।लेकिन, ऐसा होना संयोग हर्गिज नहीं है। बेशक, अमित शाह भारत के गृहमंत्री हैं, लेकिन शाह आरएसएस के परखे हुए स्वयंसेवक पहले हैं। और आरएसएस के शीर्ष हलके अब हिटलर की विचार तथा आचार की परंपरा से अपने रिश्तों को छुपाने की चाहे जितनी कोशिश क्यों न करें, लेकिन खुद को हिटलर के प्रचार मंत्री, गोयबल्स का सच्चा चेला साबित करने में हमेशा लगे रहते हैं। शाह ने अपने व्याख्यान में और उस पर आधारित ट्वीट में भी दावा किया था कि आजादी के बाद से भारत में मुसलमानों का अनुपात बढ़ता ही गया है और हिंदुओं का अनुपात तेजी से घटता जा रहा है, जोकि खतरनाक है। इस क्रम में शाह ने 1951 की जनगणना से लगाकर हिंदुओं और मुसलमानों के आबादी अनुपात के आंकड़े पेश करते हुए, बताया कि जहां हिंदुओं की आबादी जो 1951 में 84 फीसद थी, 2011 में 79 फीसद रह गयी है और इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 9.8 से बढ़कर 14.2 फीसद हो गयी है।फिर भी यहां तक तो हिंदुओं के लिए बहुत विचलित होने का कारण नहीं बनता है। बेशक, देश की कुल आबादी में हिंदुओं का अनुपात घटा है और मुसलमानों का अनुपात बढ़ा है, लेकिन दोनों की जनसंख्याओं में अंतर इतना बड़ा है कि ये आंकड़े शायद ही खास चिंता पैदा करेंगे। आखिरकार, साठ साल में आबादी में मुसलमानों का अनुपात कुल 4.4 फीसद बढ़ा है और हिंदुओं का अनुपात इससे कुछ कम ही घटा है। और साठ साल की कमी और बढ़ोतरी के बावजूद, हिंदू आबादी 80 फीसद के करीब है, जबकि मुस्लिम आबादी 14 फीसद से थोड़ी सी ज्यादा ही है। अगर हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की आबादी बढ़ने की यही रफ्तार रहती है जो कि होना, जैसाकि हम आगे देखेंगे, असंभव है तब भी सरल गणित के हिसाब से भारत में मुसलमानों की आबादी को हिंदुओं की आबादी के बराबर होने में कम से कम साढ़े पांच सौ साल तो जरूर लग जाएंगे। जाहिर है कि इतनी दूर का खतरा दिखाकर, अगले ही महीने होने वाले चुनाव में वोट हासिल करने की, बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है।

ललित सुरजन की कलम से - केन्द्र-राज्य संबंध और क्षेत्रीय दल

वास्तव में न पांच सौ साल में, न हजार साल में, तार्किक रूप से आबादी में मुसलमानों का हिस्सा कभी भी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होने वाला है। और इसकी सीधी से वजह यह है कि कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा आजादी के बाद से बढ़ता जरूर रहा है, लेकिन यह रुझान

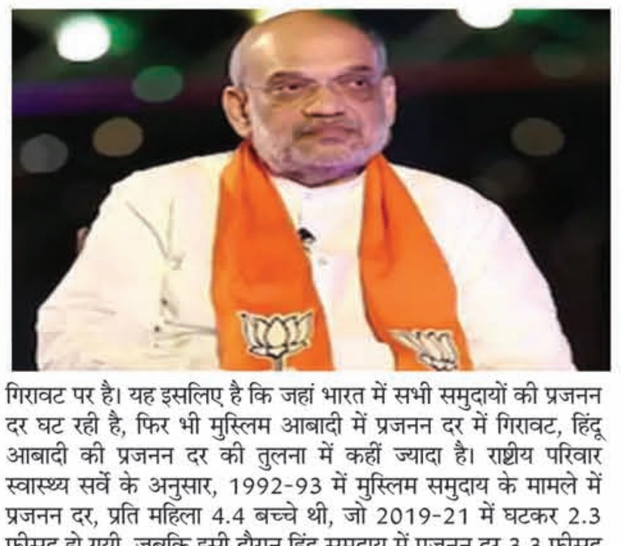

गिरावट पर है। यह इसलिए है कि जहां भारत में सभी समुदायों की प्रजनन दर घट रही है, फिर भी मुस्लिम आबादी में प्रजनन दर में गिरावट, हिंदू आबादी की प्रजनन दर की तुलना में कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार, 1992-93 में मुस्लिम समुदाय के मामले में प्रजनन दर, प्रति महिला 4.4 बच्चे थी, जो 2019-21 में घटकर 2.3 फीसद हो गयी, जबकि इसी दौरान हिंदू समुदाय में प्रजनन दर 3.3 फीसद से घटकर 1.9 पर आ गयी। इस तरह, मुस्लिम समुदाय में प्रति महिला 2.1 बच्चों के जन्म की कमी दर्ज की गयी, जबकि हिंदुओं के मामले में यही कमी 1.4 प्रति महिला थी। इसलिए, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब हिंदू और मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर बराबर हो जाएगी और आबादी अनुपात में किसी उल्लेखनीय घटत-बढ़त का किस्सा ही खत्म हो जाएगा।

बहरहाल, शाह तो धड़ से यह दावा कर देते हैं कि भारत में मुस्लिम आबादी 24.6 फीसद पर पहुंच गयी है। यह बढ़ोतरी घुसपैठ की वजह से हुई है।% देश के गृहमंत्री उस समुदाय की आबादी में पिछले डेढ़ दशक में 10 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी का दावा कर रहे थे, जिसकी आबादी साठ साल में कुल 4 फीसद बढ़ी थी ! बेशक, शाह ने इसमें यह और जोड़ा था कि यह बढ़ोतरी घुसपैठ का नतीजा है। फिर भी यह बढ़ोतरी भारत की आबादी का 10 फीसद यानी 14 करोड़ होती है पर बंगलादेश की तो कुल आबादी ही 17 करोड़ है। क्या बंगलादेश की सारी आबादी घुसपैठ कर के भारत में आ गयी है? यह तो बंगलादेश और पाकिस्तान की कुल आबादी के करीब तिहाई के बराबर होता है। और तो और संघ परिवार के अफवाही प्रचार में भी कभी घुसपैठियों का करोड़-दो करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा नहीं सुना गया पर यहां 14 करोड़ घुसपैठियों का दावा किया जा रहा था।झूठ पकड़े जाने पर शाह को शर्मिंदगी से बचने के लिए ट्वीट का संबंधित हिस्सा छुपाकर भागना पड़ा। लेकिन, इस सब के बीच एक जरूरी सवाल और उठ गया है, जिसका जवाब शाह और मोदी कभी नहीं देंगे। 2011 के बाद यानी जिन कुल 14 सालों में घुसपैठियों की संख्या में करीब 14 करोड़ की बढ़ोतरी का अमित शाह दावा कर रहे थे, उनमें से 11 साल से ज्यादा से तो देश में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ही है। और सभी जानते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा, खासतौर पर घुसपैठ के खिलाफ सीमाओं की सुरक्षा, केंद्र सरकार की और उसमें भी खासतौर पर उस गृह मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है, जिसके मुखिया छ- साल से ज्यादा से खुद अमित शाह ही हैं। उनकी नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ कैसे चलती रही? अगर इस पैमाने की घुसपैठ का दावा वाकई सच है, तो क्या मोदी सरकार को और खासतौर पर शाह को, इस कथित घुसपैठ की जिम्मेदारी कबूल कर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। लेकिन, गंभीरता से जिम्मेदारी संभालने के अर्थ में, जिस अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का इतना शोर मचाया जाता है, उसके मोर्चे पर भी मोदी सरकार का प्रदर्शन, उसके सांप्रदायिक प्रचार के विपरीत, काफी निराशाजनक ही रहा है। सिर्फ एक आंकड़ा इसे साफ कर देगा। 2003 से 2013 तक यानी 9 साल में, पूर्ववर्ती सरकार ने 88,792 अवैध बंग्लादेशी प्रवासियों का प्रत्यार्पण किया था। लेकिन, मोदी राज में 2014 से 2019 तक, 6 साल में इसके तिहाई से भी कम, कुल 2,566 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का ही प्रत्यार्पण किया गया था।

प्रत्यार्पण की दर में यह कमी, अगर मोदी सरकार की अक्षमता को नहीं, तो जरूर कथित घुसपैठ में कमी को दिखाती है।बेशक, देश के मौजूदा शासकों को जवाब तो इसका भी देना चाहिए कि क्या वजह है कि 2011 के बाद, जो दशकीय जनगणना 2011 में पूरी हो जानी चाहिए थी, 2026 में ही कहीं जाकर शुरू होने वाली है? बेशक, 2020 में कोरोना के विस्फोट के चलते जनगणना का काम रुक गया था। लेकिन, उसके बाद तो पूरा आधा दशक गुजर चुका है। सच्चाई यह है कि हमारे अड़ोस-पड़ोस के छोटे-छोटे देशों ने भी इस बीच जनगणना कराई है और भारत संभवतः ऐसे बहुत थोड़े से अपवादों में से है, जहां जनगणना अब तक कोरोना की बाधा से उबर नहीं पाई है।

पीड़ित छात्रा को घटनास्थल पर लेकर पहुंची पुलिस, जुटाए सबूत

एजेंसी

नई दिल्ली। साउथ दिल्ली स्थित निजी यूनिवर्सिटी की बीटेक छात्रा के साथ गैंगरेप प्रयास मामले की जांच हर पहलू को ध्यान में रखकर की जा रही है। यूनिवर्सिटी से सुरक्षा स्टाफ व नॉन टीचिंग स्टाफ की जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस टीम पीड़ित छात्रा घटनास्थल पर भी लेकर गई। जिससे पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। घटना के संबंध में जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें 67 गार्ड, छात्र तथा केयर टेकर शामिल हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी कैमरा फुटेज की भी गहनता से जांच की जा रही है। छात्रा को भेजे गए धमकी भरे ईमेल व मैसेज की जांच का जिम्मा साइबर टीम को सौंपा गया है। पुलिस को शक है कि छात्रा को एक ही आईपी एड्रेस से ईमेल भेजे गए थे। वहीं, कॉलेज की इंटरनल जांच कमेटी ने भी जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि पुलिस को मैदानगढ़ी स्थित निजी यूनिवर्सिटी में बीटेक की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की सूचना मिली थी। कॉलेज पहुंचने पर पता चला घटना साढ़े दस बजे की है। काउंसलिंग के बाद छात्रा ने सोमवार देर रात बयान दर्ज कराया कि कन्वेंशन सेंटर के समीन कंस्ट्रक्शन साइट पर गार्ड समेत चार लोगों ने उसके साथ गैंगरेप का प्रयास किया था।

एमसीडी कर्मचारियों को दिया दिवाली तोहफा, जारी किया बोनस

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने घोषणा की कि इस वर्ष दिल्ली नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को दिवाली के शुभ अवसर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस समय से पहले जारी कर खुश कर दिया है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि अब तक कुल 48.70 करोड़ रूपये की राशि निगम मुख्यालय, जोनल कार्यालयों और अस्पतालों के कर्मचारियों को सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी है। यह समय से पूर्व बोनस वितरण निगम की कर्मचारी कल्याण प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राजा इकबाल सिंह ने डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते इस प्रगतिशील कदम को रेखांकित करते हुए बताया कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार वित्त विभाग ने ऑनलाइन बोनस बिल जनरेशन और भुगतान प्रणाली को अपने पे मॉड्यूल के माध्यम से लागू किया है। इस नवाचार ने बोनस भुगतान की प्रक्रिया को तेज, सुगम और पारदर्शी बनाया है। महापौर ने कहा कि इस नए वित्तीय मॉड्यूल के जरिए बोनस भुगतान समय पर क्रेडिट हुआ हैं, जिससे कर्मचारियों को उनका दिवाली उपहार सही समय पर प्राप्त हुआ है। इस मॉड्यूल में ड्रॉइंग और डिस्बर्सिंग अधिकारियों को न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त, पुनः नियुक्त और दिवंगत कर्मचारियों के लिए भी बोनस बिल तैयार करने की सुविधा प्राप्त है। इस मॉड्यूल से बिल प्रक्रिया सरल और तीव्र हो गई है। साथ ही, बिलों की आसानी से पुनः प्राप्ति और रिकॉर्ड रखरखाव प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देता है।

भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में दो कार्डबोर्ड फैक्ट्रियों में लगी आग

नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित दो कार्डबोर्ड फैक्ट्रियों में मंगलवार देर रात आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा परिसर लपटों से घिर गया। दमकल विभाग को रात करीब 8 बजकर 16 मिनट पर घटना की सूचना मिली थी। बढ़ती आग को देखते हुए इसे बड़ी कॉल घोषित कर मौके पर 24 दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। दमकल विभाग के अनुसार, यह आग के- 442, भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित दो आपस में जुड़ी कार्डबोर्ड फैक्ट्रियों नंबर 422 और 423 में लगी थी। दोनों फैक्ट्रियां करीब 250-250 गज में बनी हुई थीं। दोनों में बेसमेंट के अलावा ऊपर चार मंजिला बना हुआ था। घटना स्थल पर शुरुआत में एसटीओ परास और एसओ वीरेंद्र के नेतृत्व में टीम पहुंची। दमकल अधिकारी के अनुसार करीब सात घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुधवार तड़के 2-40 बजे काबू किया गया। अंतिम चरण में एडीओ सुमन और एसटीओ अमित के नेतृत्व में राहत दलों ने मोर्चा संभाला। दमकल विभाग के अनुसार बुधवार सुबह 3-55 बजे आग को पूरी तरह बुझा दिया गया और कूलिंग ऑपरेशन शुरु किया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शुरुशाती जांच में शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

गोवा के मंत्री रवि नाइक के निधन पर दिल्ली के महापौर ने जताया शोक

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनकी कमी गहराई से महसूस की जायेगी। महापौर राजा इकबाल सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि रवि नाइक (79 वर्ष) के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। एक अनुभवी नेता, जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने गोवा के विकास में स्थायी योगदान दिया और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उनकी कमी गहराई से महसूस की जायेगी। मेरी प्रार्थनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। उल्लेखनीय है कि रवि नाइक पोंडा विधानसभा से 7 बार विधायक रहे और दो बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। 1984 में वो पहली बार महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के टिकट पर पोंडा से विधायक चुने गए।

अक्षय पात्र फाउंडेशन ने अटल बंगाली स्कूल के बच्चों में वितरित किया 4600 स्टेनलेस स्टील प्लेट

एजेंसी

नई दिल्ली। अटल बंगाली स्कूल में विद्यार्थियों के लिए 4,600 स्टेनलेस स्टील प्लेटों का विशेष वितरण कार्यक्रम अक्षय पात्र फाउंडेशन ने आयोजित किया। यह पहल विद्यालयों में छात्रों के कल्याण, स्वच्छता और पुन- उपयोग योग्य (सस्टेनेबल) संसाधनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में शिक्षा निदेशक कृतिका चौधरी, अक्षय पात्र से सुंदर गोपाल दास और एक्सपो फ्रेट लिमिटेड (इएफएल) के प्रतिनिधि जीएम एचआर सुनिल थॉमस विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर डीईओ रमेश चंद्रा, विद्यालय की प्रधानाचार्या रितू गुप्ता एवं विमल आहूलवालिया की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ सुंदर गोपाल दास ने सभी अतिथियों के स्वागत से किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या रितू गुप्ता ने स्वागत

भाषण देते हुए अक्षय पात्र फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात् सुंदर गोपाल दास ने कहा कि अक्षय पात्र का उद्देश्य केवल बच्चों को भोजन कराना नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर प्रेरित करना है। ईएफएल के प्रतिनिधि जीएम एचआर सुनिल थॉमस ने बच्चों के कल्याण में योगदान देने पर संतोष व्यक्त किया। एनडीएमसी की शिक्षा निदेशक कृतिका चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन ने पिछले छह वर्षों से विद्यार्थियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया है और उन्हें सबसे बेहतरीन मिड-डे मील उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के अंतर्गत बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने पर जोर दिया है। एक स्वस्थ और स्वच्छ मिड-डे मील सुनिश्चित करना न केवल एक बड़ा लक्ष्य है, बल्कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। अक्षय पात्र के माध्यम से हम बच्चों को साफ-सुथरा और पोषणयुक्त भोजन प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों से पूछा 'क्या आपको यह भोजन पसंद आया? स्वादिष्ट है?' सभी बच्चों ने हाँ में उत्तर दिया। यह दर्शाता है कि स्वस्थ और पौष्टिक भोजन बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वे पढ़ाई और ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं।

दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताया आभार

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान की है। इस फैसले को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बताते हुए मुख्यमंत्री ने 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु उच्चतम न्यायालय का आभार। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर लोगों के उत्साह और भावनाओं का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि वह जनभावनाओं का पूरा सम्मान करेगी, लेकिन स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प से कभी समझौता नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि इस दीपावली पर ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, ताकि त्योहारों की रौनक बनी रहे और पर्यावरण सुरक्षित हो। उनका लक्ष्य है कि सभी मिलकर उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें।

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की मंजूरी पर मंत्रियों ने जताया आभार

एजेंसी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर हरित पटाखों के उपयोग और बिक्री की अनुमति प्रदान करने पर दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने न्यायालय का आभार जताया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे आठ साल बाद दिल्लीवासियों के लिए खुशियों वाली दीपावली बताया। साथ ही कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदलते ही प्रतिबंध खत्म हो गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में पटाखे जलाने की अनुमति दी है। 8 साल बाद अब दिल्लीवासी पटाखे जला पाएंगे। यह दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स चैनलों के माध्यम से बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। लाइसेंस प्राप्त पटाखा निर्माताओं को सुनिश्चित करना होगा कि केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं। यदि कोई सामान्य पटाखों की बिक्री पकड़ा जाता है, तो पटाखों का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(एसपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) मिलकर प्रदूषण स्तर और एक्यूआई रीडिंग की निगरानी करेंगे। सिरसा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपील की है कि सब मिलकर पर्यावरण का ध्यान रखते हुए दीपावली के इस त्योहार की रौनक बढ़ाएंगे।

पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि सभी दिल्लीवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने दिल्ली में एक अच्छी सरकार चुनी है और सरकार के प्रयास सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस बार लोग बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं। पिछली सरकार भी ऐसा कर सकती थी। आज यह साबित हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। पहली बार सरकार बदली और सरकार बदलते ही दिवाली पर प्रतिबंध खत्म हो गया।

डीयू की वीसीआईएस के लिए 2280 विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम (वीसीआईएस) पार्ट टाइम 2025-26 के लिए चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. रंजन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस बार 3500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 2280 विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट किए गए। आवेदकों को 13 से 15 अक्टूबर तक ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया गया था। ग्रुप डिस्कशन अब पूर्ण हो चुका है। आगामी दिनों में चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चयन के बाद वीसीआईएस पार्ट टाइम इंटर्न को दिल्ली विश्वविद्यालय के 55 से अधिक विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से इस वाइसचांसलर इंटर्नशिप स्कीम (वीसीआईएस) की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर कार्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इससे उन्हें विशेष रूप से विश्वविद्यालय प्रणाली

के विभिन्न क्षेत्रों और सामान्य रूप से सरकारी व्यवस्थाओं में आधिकारिक कामकाज को समझने में मदद मिलती है। डीएसडब्ल्यू कार्यालय दो प्रकार की वीसीआईएस इंटर्नशिप प्रदान करता है। शैक्षणिक सत्र के दौरान छह महीने के लिए वीसीआईएस पार्ट टाइम इंटर्नशिप और गर्मी की छुट्टियों के दौरान दो महीने के लिए फुल टाइम वीसीआईएस ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप। अंशकालिक इंटर्नशिप के लिए प्रति सप्ताह 8-10 घंटे लचीले कार्य घंटे हैं, जिसमें प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को 5775 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलता है और ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए प्रति सप्ताह 20 घंटे कार्य घंटे हैं, जिसमें 11,000 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलता है।

एसएयू में छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में अभाविप ने विवि प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

एजेंसी

नई दिल्ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) नीत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के प्रतिनिधिमंडल ने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी (एसएयू) में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना के संबंध में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो. केके अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर त्वरित एवं कठोरतम कार्रवाई की मांग की। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष आर्यन मान ने कहा कि यह घटना न केवल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे शिक्षा जगत के लिए कलंक है। छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा पर किसी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में आज अभाविप ने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से मिलकर छात्रा को न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) प्रत्येक छात्र और छात्रा की सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जब तक

पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक डूसू और अभाविप दोनों न्याय की इस लड़ाई को हर स्तर पर जारी रखेंगे। अभाविप की मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और विश्वविद्यालयों में भयमुक्त एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। आर्यन मान ने कहा कि अभाविप का मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार की घटनाएं किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। परिषद सदैव विश्वविद्यालय परिसरों में छात्राओं की सुरक्षा एवं सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है और इस दिशा में निरंतर कार्यरत है। अभाविप की स्पष्ट मांग है कि पीड़िता को शीघ्र न्याय मिले, अन्यथा विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर न्यायालय तक अपनी आवाज बुलंद करेगी और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी। अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खारवाल ने कहा कि आज अभाविप नीत डूसू प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रो. केके अग्रवाल से भेंट कर छात्रा को न्याय दिलाने के लिए अपनी चार सूत्रीय मांगें रखीं। शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की घृणित घटना सभी के लिए शर्मसार करने वाली है। पूरा छात्र समुदाय, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और अभाविप पीड़िता के साथ मजबूती से खड़े हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि वह शीघ्र और निर्णायक कदम उठाए।

एनडीएमसी ने सब-वे और एफओबी के एस्केलेटरों को फिर से चालू करने का लिया फैसला

एजेंसी

नई दिल्ली। नागरिकों की सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने क्षेत्र में स्थित सभी सब-वे और फुटओवर ब्रिज (एफओबी) के एस्केलेटरों को शीघ्र सुचारु रूप से चालू करने का निर्णय लिया है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि परिषद इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' विजन के अनुरूप जनता को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र के प्रमुख सब-वे में कुल 22 एस्केलेटर लगाए गए हैं, जिनमें से वर्तमान में 13 चालू हैं। 2 एस्केलेटरों में तकनीकी खराबी है, जबकि 7 एस्केलेटर तकनीकी समस्याओं और सुरक्षा कारणों से लंबे समय से बंद पड़े हैं। इन बंद एस्केलेटरों की मरम्मत व पुनः चालू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है, जिससे लोगों को अधिकतम सुविधा मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त, एनडीएमसी क्षेत्र में 4 फुटओवर ब्रिजों पर भी एस्केलेटर स्थापित हैं, जो डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और मदर टेरेसा क्रेसेंट के पास स्थित हैं। इनमें से 2 एस्केलेटर एक आरएमएल अस्पताल के पास और दूसरा मदर टेरेसा क्रेसेंट के पास तकनीकी कारणों से बंद हैं। मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है। आरएमएल अस्पताल के पास का एस्केलेटर नवंबर के अंत तक चालू हो जाएगा।

उप महापौर ने केशवपुरम जोन के वार्ड का किया निरीक्षण, की नागरिक सुविधाओं की समीक्षा

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली के उप महापौर जय भगवान यादव ने केशवपुरम जोन के अशोक विहार वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने नागरिक समस्याओं और औद्योगिक क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय निवासियों ने वजीरपुर के मछली बाजार में टूटी नाली के कारण खराब सफाई व्यवस्था और जलभराव की जानकारी दी। मामले का संज्ञान लेते हुए, उप महापौर ने डीएसआईआईडीसी के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और टूटे हुए नाले की जल्द से जल्द मरम्मत करने के निर्देश दिए। उप महापौर जय यादव ने कहा कि वार्ड में सफाई कर्मचारियों और मशीनों की कमी है। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में कचरे का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुपर सकर मशीनें और सफाईकर्मी तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने 3 से 4 दिनों के भीतर नाले की तत्काल मरम्मत और सफाई के निर्देश दिए। उप महापौर ने वार्ड में झुग्गी कॉलोनी और रेलवे ट्रैक के पास सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और जाना कि कई सड़कें जर्जर अवस्था में हैं जिससे जलभराव हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गड्ढों की समस्या का समाधान करने और खुले में पड़े कचरे का नियमित

निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बोलते हुए उप महापौर जय भगवान यादव ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और क्षेत्र के सभी विकास संबंधी मुद्दों का तत्काल समाधान करेंगे। उप महापौर ने अधिकारियों को मुख्य सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए ताकि यातायात जाम से बचा जा सके और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय के लिए अगले सप्ताह सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ विधायक पूनम शर्मा, केशवपुरम क्षेत्र के उपायुक्त संदीप कुमार, डीएसआईआईडीसी के अधिकारी और क्षेत्र के विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

गुजरात के कारोबारी के अपहरण में वांछित कुख्यात अपराधी 'टाइगर' गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात के गांधीधाम से कारोबारी के अपहरण में वांछित कुख्यात अपराधी तुशांत वासु उर्फ सूरज उर्फ टाइगर (32) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक अत्याधुनिक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपित राजस्थान के बीकानेर जिले के बाज्जू तेजपुरा गांव का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी के अनुसार 16 जुलाई 2025 को गांधीधाम, कच्छ (गुजरात) में चार लोगों ने दो कारों में सवार होकर एक व्यापारी का उसके दफ्तर के बाहर से अपहरण कर लिया था। इस संबंध में थाना गांधीधाम (कच्छ पूर्व) में मुकदमा दर्ज किया गया था। इधर स्पेशल सेल को 15 अक्टूबर को सूचना मिली कि कुख्यात अपराधी टाइगर रोहिणी इलाके में अवैध हथियारों के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने छापा मारा और आरोपित को रोहिणी क्षेत्र से दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में

आरोपित ने बताया कि वह अब तक 16 से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। जिनमें हत्या का प्रयास, लूट, चोरी और हथियार कानून के मामले शामिल हैं। वह पहले सनारिया जेल (हरियाणा) में बंद रह चुका है। जमानत पर रिहा होने के बाद वह गांधीधाम गया, जहां उसकी मुलाकात मोरबी के हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह झाला से हुई। दोनों ने मिलकर व्यापारी के अपहरण की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। बाद में व्यापारी को छोड़ दिया गया था। पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपित पर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। स्पेशल सेल अब आरोपित के अन्य साथियों और नेटवर्क की जांच में जुटी है।

दिल्ली सरकार ने 12 वित्तपोषित कॉलेजों को तीसरी किश्त में 108 करोड़ रुपये किए जारी, कुल 325 करोड़ की सहायता

एजेंसी

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने अपने 12 पूर्ण रूप से वित्तपोषित कॉलेजों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी किश्त के रूप में 108 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी करने के आदेश दे दिए हैं। अब तक तीनों किस्तों से इन कॉलेजों को कुल 325 करोड़ की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शिक्षण संस्थानों को दिवाली का उपहार बताया, जिससे शिक्षकों के वेतन, कॉलेज विकास और बुनियादी सुविधाओं को नई गति मिलेगी।

आशीष सूद ने बताया कि यह राशि कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन, रख-रखाव तथा आवश्यक पूंजीगत व्यय के लिए दी जा रही है। इसके अलावा, बिल्डिंग रखरखाव, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए लगभग 24 करोड़ रुपये अलग से जारी किए गए हैं, ताकि सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के आधार पर हो सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसी भी शिक्षक या छात्र को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।

अनुदान प्राप्त करने वाले 12

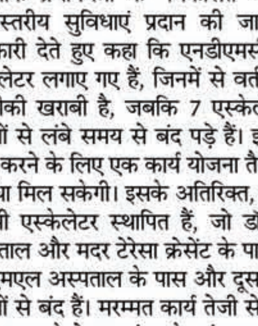

कॉलेज हैं - आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, बीआर आम्बेडकर कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सभी शिक्षण संस्थानों को समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले। इससे न शिक्षकों-कर्मचारियों को असुविधा हो और न छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा आए।

उन्होंने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी (आआपा) अनुदान समय पर जारी नहीं करती थीं या बिल्कुल नहीं देतीं, जिससे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होता था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें उपेक्षा का शिकार रही, बहाने बनाते और राजनीतिक माइलेज के लिए काम करतीं। ढांचागत विकास पर ध्यान न देने से कॉलेजों की स्थिति बदतर हो गई। सूद ने कहा कि भाजपा की सरकार ने आते ही बुनियादी सुविधाओं का आंकलन किया और वित्तीय समृद्धि सुनिश्चित की, ताकि अच्छे व काबिल विद्यार्थी तैयार हों।

महिला से शादी करने के लिए बच्चे को किया अगवा, गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। । दक्षिणी पूर्वी जिले के अमर कॉलोनी थाना पुलिस ने एक 4 वर्षीय अपहृत बच्चे को उसके अपहरण के मात्र 8 घंटे के भीतर लखनऊ (उप्र) से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहरणकर्ता सुधाकर सिंह को भी गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपित बच्चे की मां से शादी करना चाहता था। दबाव बनाने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। दक्षिणी पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी ने आज बताया कि यह घटना 12 अक्टूबर की है। अमर कॉलोनी थाने में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। जांच में पता चला कि बच्चे की मां पिछले लगभग एक साल से आरोपित सुधाकर सिंह के साथ इंस्टाग्राम पर संपर्क में थी। सुधाकर सिंह अक्सर बच्चे के पिता को धमकाता था कि यदि उनकी पत्नी ने उससे संबंध नहीं रखे तो वह उनके बेटे को अगवा कर लेगा। घटना वाले दिन, दोपहर करीब 1:00 बजे, बच्चे के पिता ने आरोपित सुधाकर सिंह को अपने घर के पास देखा, लेकिन वह भाग गया। शाम 4:30 बजे पीड़ित को पत्नी का फोन आया। जिसने बताया कि सुधाकर सिंह ने उनके बेटे को घर के बाहर खेलते समय अगवा कर लिया है। इसके तुरंत बाद अमर कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी और मानवीय सूचना तंत्र का इस्तेमाल करते हुए आरोपित के मूवमेंट को ट्रैक किया। लगातार प्रयासों से पुलिस टीम आरोपित सुधाकर सिंह के मार्ग का पता लगाने में सफल रही और 8 घंटे के भीतर उसे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सुहैलदेव एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर से धर दबोचा गया। बच्चे को सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया गया। सख्ती से पूछताछ के दौरान आरोपित सुधाकर सिंह ने खुलासा किया कि उसने बच्चे को इसलिए अगवा किया था ताकि वह डरा कर उसकी मां पर शादी करने का दबाव बना सके।

हर सफर बन जाएगा यादगार

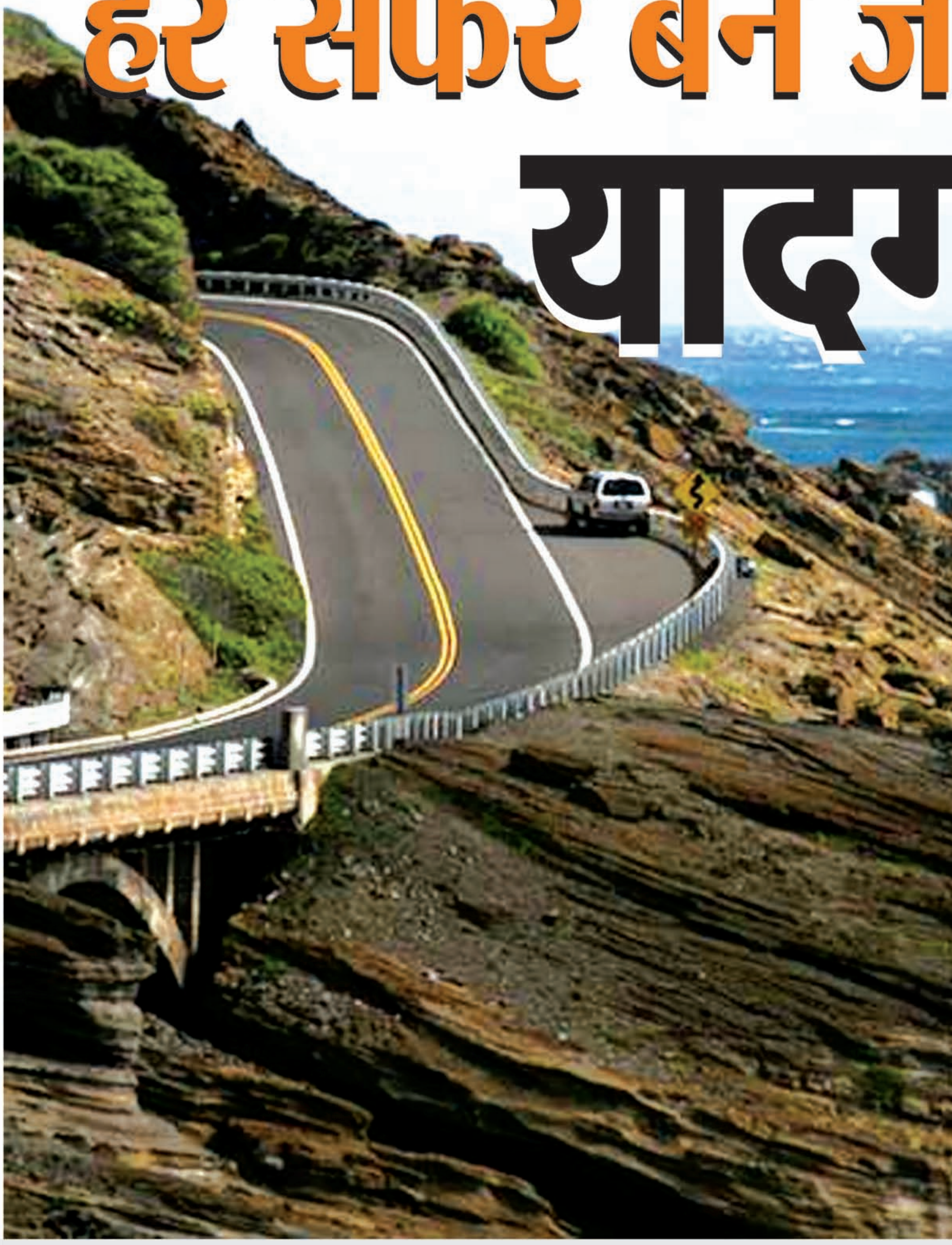

सफर करने के बारे में सबसे मजेदार बात है, हर कदम पर किसी नई खोज का रोमांच। फिर चाहे वह किसी बच्चे द्वारा ट्रेन की खिड़की से पहली बार खुले में ऊँटों को चरते देखने का रोमांच हो या फिर पहली-पहली बार किसी अजनबी देश में कदम रखने पर नजर आने वाली एक अलग दुनिया का रोमांच।

यूँ इंसान अपने घर, अपने जाने-पहचाने माहौल के सुरक्षा कवच में सबसे सहज महसूस करता है, लेकिन नएपन की लालसा भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ नया देखने की लालसा ही उसे दुनिया घुमा लाती है।

कभी आदिमानव कुछ नया तलाशने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल जाता था। आज उसका वंशज महासागर की गहराइयों में गोता लगा चुका है और अंतरिक्ष के निर्वात अंधकार में चहल-कदमी कर चुका है। इन दो विपरीत छोरों के बीच आम मानव रोज कई प्रकार के छोटे-बड़े सफर करता रहता है।

जरूरी नहीं कि यात्रा कहीं दूर की हो, बोरिया-बिस्तर बाँधकर रेल, बस, जहाज या विमान से की जाए। अपने ही शहर में, कभी उन रास्तों-गलियों से निकलिए, जहाँ से आपका अब तक गुजरना नहीं हुआ है। कुछ नया दिखेगा, कोई नई खोज होगी। सोचने के नए आयाम खुलेंगे। कोई कह गया है कि सफर का उद्देश्य मंजिल पर पहुँचना नहीं, बल्कि मंजिल तक पहुँचने की प्रक्रिया का पूरा आनंद लेना होना चाहिए। जब हमारी निगाहें महज मंजिल पर टिकी होती हैं, तब रास्ते अक्सर अनदेखे रह जाते हैं... और कायनात का सारा कोलाहल, संसार का सारा स्पंदन, जिंदगी की तमाम रेलमपेल इन रास्तों पर ही तो बिखरी पड़ी है। इन्हें नहीं देखा तो सफर महज एक ठिकाना छोड़ दूसरे ठिकाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना भर हुआ, जबकि सफर मौका देता है कदम-कदम पर नए झरोखे से नया संसार देखने का, नए मित्र, नए गुरु पाने का, अनसोचे अनुभवों से गुजरकर नई जानकारी, नए ज्ञान के सागर में नहाने का। खैर, सच यह है कि लोग कई कारणों से सफर करते हैं।

कोई घर या दफ्तर के किसी कार्य विशेष के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, कोई छुट्टियों में घूमने जाने की औपचारिकता निभाने तो कोई तीर्थ करने। बहुत कम लोग सफर करने के लिए सफर पर निकलते हैं। ऐसे लोगों को न मंजिल पर पहुँचने की जल्दी होती है, न घर लौट आने की चिंता।

आप यह तय करके घर तो नहीं बैठ सकते कि कोई अच्छा अनुभव हो तो ही बाहर निकलूँ। जीवन के प्रवाह में छलाँग लगाने पर ही पता चलता है कि कब कौन-सा अनुभव अच्छा रहा और कब कौन-सा बुरा। छोटी-मोटी परेशानियाँ सफर का हिस्सा ही होती हैं। जब दुनिया को देखने, जानने निकले हैं तो इसके दोनों रूप देखने में ही तो यात्रा की परिपूर्णता होगी।

सर्दी के मौसम में आमतौर पर लोग जबर्दस्त ठंड से बचने के उपाय करते रहते हैं लेकिन इससे उलट इस मौसम का मजा भी उठाया जा सकता है। हमारे देश में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सर्दियों में सैलानी बर्फ का मजा उठाने के लिए जाना पसंद करते हैं।

सर्दियों का स्वागत करता उत्तराखंड

बर्फ का मजा उठाने के लिए पहला नाम जो हमारे जेहन में आता है वह जम्मू-कश्मीर का है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सुदूर उत्तर-पूर्व का तवांग भी सर्दियों में बर्फ का मजा लेने का अच्छा ठिकाना है। बर्फ में मौज-मस्ती का मजा ही अलग है। इससे ऊर्जा भी भरपूर मिलती है और रिश्तों में गर्माहट भी आती है।

जाड़ों में मध्य हिमालय (1200 मीटर-4000 मीटर) स्थित उत्तराखंड के कई हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत हो जाते हैं। बर्फबारी में नहाया पहाड़ तो पर्यटकों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से लेकर फरवरी के मध्य तक उत्तराखंड के कई पर्यटक स्थलों पर बर्फ गिरती है।

अंग्रेजों के बसाए शहर नैनीताल और मसूरी तो के नजदीक होने तथा रेल स्टेशनों के बिलकुल पास होने के कारण पर्यटकों की पहली पसंद हैं। इन दोनों ही शहरों तक दिल्ली से सड़क से 7 से 10 घंटे में पहुँचा जा सकता है। मसूरी तथा नैनीताल में बर्फबारी की खबर लगते ही दिल्ली, गुड़गाँव, गाजियाबाद तथा उत्तर भारत के शहरों के पर्यटक इन पर्वतीय पर्यटक स्थलों की ओर भाग पड़ते हैं। नैनीताल में बर्फ के साथ खेलने के लिए पर्यटकों की पसंदीदा जगह तो ऐतिहासिक माल रोड ही है पर यदि माल रोड में पड़ी बर्फ पर्यटकों को कम लगे तो वे नैनीताल शहर के ऊपर स्नो व्यू, टिफिन टॉप से लेकर किलवरी मार्ग पर दूर हिमालय दर्शन तक जा सकते हैं। हिमालय दर्शन से हिमालय की चोटियों का विहंगम दृश्य दिखता है। क्रिसमस के आस-पास यदि बर्फबारी हो जाए तो पर्यटक नैनीताल में त्योहार और छुट्टियों का दोगुना आनंद लेते हैं।

राजधानी देहरादून के पास मसूरी में भी साल में 3-4 बार बर्फबारी हो जाती है। बर्फबारी के होते ही पर्यटकों का हुजूम मसूरी आ जाता है। इस भीड़ से मसूरी के नीचे किंगररेग तक के रास्ते जाम हो जाते हैं। मसूरी तथा नैनीताल और उसके आस-पास सभी बजट श्रेणी में पर्याप्त होटल उपलब्ध हैं। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पर्यटक मसूरी के लाल टिब्बा, किनोग हिल, जॉर्ज एवरेस्ट, गन हिल तथा क्लाउड ऐंड स्थानों पर जाते हैं।

मसूरी से 32 किमी दूर स्थित नव पर्यटक स्थल धनौल्टी तक बर्फबारी के बीच सड़क के दोनों ओर बर्फ जम जाती है। इस मार्ग पर तब गाड़ी चलाने का आनंद दोगुना हो जाता है। चमोली जिले के जोशीमठ से 15 किमी दूर औली तो अब विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग केंद्र तथा शीतकालीन रिजॉर्ट का रूप ले चुका है।

यहाँ 2010 के जनवरी-फरवरी में शीतकालीन सैफ खेलों का आयोजन होना है। औली में स्कीइंग के 7 दिवसीय, 14 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए तथा पर्यटकों के लिए एक-दो दिवसीय स्कीइंग करने की सुविधा गढ़वाल मंडल विकास निगम उपलब्ध कराता है। विद्यार्थियों के लिए तो रहने, खाने की सुविधा, उपकरणों, स्की लिफ्ट की उपलब्धता मय शिक्षक 5,500 रुपए में उपलब्ध है। पर्यटकों को बेशक एक या दो दिन स्की करने के लिए तथा हर सुविधा के लिए अलग भुगतान करना पड़ता है। रोप वे द्वारा औली पहुँच कर पर्यटक नई दुविधा में होता है।

सामने नंदा देवी सहित कई हिमाच्छादित चौटियों का दृश्य दिखता है। औली में 1,300 मीटर लंबा स्कीइंग ट्रैक उपलब्ध है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 800 मीटर लंबी चियर लिफ्ट के अलावा स्कीयरों को ऊपर पहुँचाने के लिए दो स्की लिफ्ट उपलब्ध है।

कुल मिलाकर औली में कम दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्की रिजॉर्ट का मजा लिया जा सकता है इसलिए विदेशी पर्यटक भी अपने देशों में महँगे स्की रिजॉर्टों में जाने के बजाय औली आकर स्कीइंग करके पैसा बचाते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव उत्पल कुमार सिंह बताते है कि शीतकालीन सैफ खेलों के आयोजन की तैयारियों के पूरा होने के साथ औली शीतकालीन खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित हो जाएगा।

औली के अलावा उत्तराखंड में उत्तराकाशी जिले का दयारा बुग्याल, देहरादून में चकराता के पास मुंडाली, रूद्रप्रयाग जिले का चोफता तथा पिथौरगढ़ मुंस्यारी के पास खलिया टॉप स्कीइंग के शौकीनों के लिए पसंदीदा पर्यटक स्थल है। अंग्रेजों के समय के स्थापित पर्यटक स्थलों के अलावा उत्तराखंड में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए अनगिनत स्थल है। इनमें से कई स्थल तो अभी पर्यटक मानचित्र पर आ भी नहीं पाए है। स्थली मुखवा में भी जाड़ों में अच्छी-खासी बर्फ पड़ती है।

वित्त मंत्री ने कर्नाटक के कोप्पल में किसान प्रशिक्षण एवं कृषि प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया

एजेंसी
नई दिल्ली। कर्नाटक के चार दिवसीय दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोप्पल जिले के मेथागल गांव में कृषि प्रसंस्करण के लिए किसान प्रशिक्षण सह सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र स्थानीय किसानों को उनकी उपज का मूल्य बढ़ाने में मदद करने में अहम भूमिका निभाएगा। किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर सीतारमण ने कहा कि यह पहल फल-आधारित उद्यमों के लिए एक स्थायी, बाजार-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य फल-आधारित उद्यमों के लिए एक स्थायी, बाजार-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, किसानों को सशक्त बनाना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) योजना के तहत वित्त पोषित, किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की शुरुआत की गई है। यह आधुनिक फल प्रसंस्करण और विपणन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

ग्लोबल मार्केट में पहली बार 4,200 डॉलर के पार पहुंचा सोना, नए शिखर चांदी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार और वायदा बाजार में तो सोना लगातार मजबूती के नए रिकॉर्ड बना ही रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी इस चमकीली धातु ने जबरदस्त छलांग लगाई है। सोने ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिजिकल गोल्ड (हाजिर सोना) की कीमत आज 4,209.66 डॉलर प्रति औंस के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, बाद में इस चमकीली धातु की कीमत में मामूली गिरावट भी आई, जिसकी वजह से भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,204.91 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था। सोने की तरह ही चांदी की कीमत ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त तेजी दिखाई है। आज के कारोबार में चांदी की कीमत 53.54 डॉलर प्रति औंस के ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच गई। हालांकि बाद में इसके भाव में भी गिरावट आई। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे चांदी 52.97 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत 27.50 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर थी। इस तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत पिछले एक साल के दौरान लगभग दोगुनी हो गई है।

सितंबर में यात्री वाहनों की बिक्री चार फीसदी बढ़कर 3,72,458 इकाई रही: सियाम

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री सितंबर महीने में सालाना आधार पर चार फीसदी बढ़कर 3,72,458 इकाई रही है। उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने जारी आंकड़ों में बताया कि सितंबर में निर्माताओं से डीलरों तक यात्री वाहनों की शिपमेंट में सालाना आधार पर चार फीसदी की वृद्धि देखी गई। उद्योग निकाय ने कहा कि सितंबर में कुल 3,72,458 इकाइयां भेजी गई, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान यह संख्या 3,56,752 थी। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में दोपहिया वाहनों की बिक्री 7 फीसदी वृद्धि के साथ 21,60,889 इकाई रही, जबकि सितंबर, 2024 में यह 20,25,993 इकाई रही थी। ये वृद्धि ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेतक है, जो बढ़ती उपभोक्ता मांग और बाजार की मजबूती को दर्शाती है। सियाम ने कहा कि यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी ऑटोमोटिव उद्योग के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है, क्योंकि निर्माता चुनौतियों का सामना करने और बाजार में मौजूद अवसरों का लाभ उठाने में लगे हुए हैं। ये आंकड़े उद्योग के भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाते हैं।

बीएलएस इंटरनेशनल को मिला चीन में भारतीय वीजा केंद्रों के परिचालन का ठेका

नई दिल्ली। टेक-आधारित सेवा प्रदाता कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों की स्थापना और परिचालन का तीन साल का ठेका मिला है। कंपनी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह ठेका 14 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। समझौते की शर्तों के तहत उसे चीन की राजधानी बीजिंग के अलावा शंघाई और ग्वांग्झू में भी वीजा आवेदन केंद्रों की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी दी गयी है। विभिन्न देशों की सरकारों और मिशनों को वीजा, दूतावासों से संबंधित तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली बीएलएस इंटरनेशनल के संयुक्त प्रबंध निदेशक शिखर अग्रवाल ने इसे कंपनी के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने इसके लिए विदेश मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। ठेका मिलने की घोषणा के बाद आज कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत की जबरदस्त उछाल देखा गया। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कंपनी को दो साल के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों से संबंधित किसी भी ठेके के लिए बोली लगाने से प्रतिबंधित कर दिया था जिसके बाद कंपनी के शेयर 18 फीसदी से अधिक टूट गये थे। हालांकि यह प्रतिबंध सिर्फ नयी निविदाओं पर लागू होंगे। उल्लेखनीय है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के कुल राजस्व में भारतीय मिशनों का योगदान लगभग 12 प्रतिशत और परिचालन लाभ में आठ प्रतिशत था।

आईएमएफ का वृद्धि अनुमान बढ़ाना भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमाणः पीयूष गोयल

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) का चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.6 फीसदी करना देश की आर्थिक मजबूती और मजबूत बुनियादी ढांचे का प्रमाण है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 6.6 फीसदी कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले पांच तिमाहियों में सबसे

अधिक है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि देश में निवेश, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और जीएसटी में कटौती के कारण आर्थिक आत्मविश्वास को दर्शाती है। इसी महीने विश्व बैंक ने भी भारत के वृद्धि अनुमान को 6.3 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 फीसदी किया था। गोयल ने उद्योग से वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नेतृत्व करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कभी-कभी उद्योग मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में मामूली रियायतों को लेकर अनावश्यक आपत्ति करता है, जो देश की कमजोर छवि पेश करता है। उन्होंने आपूर्ति शृंखला की मजबूती और विविधीकरण पर जोर देते हुए कहा कि एक ही आपूर्तिकर्ता या सीमित देशों पर निर्भरता से इस क्षेत्र में जोखिम उत्पन्न हो सकता है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि कुछ उत्पादों के लिए घरेलू संरक्षण जरूरी हो सकता है लेकिन अन्य मामलों में उद्योग को वैश्विक बाजारों के साथ जुड़े रहकर अपनी दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''हम निश्चित रूप से अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की कृपा पर नहीं रहना चाहते हैं जो किसी एक उद्योग को पंगु बना दे। हालांकि, कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, जिन्हें ठोस संरक्षण की जरूरत है।'

खान मंत्रालय ने राज्य खनन तैयारी सूचकांक और राज्य रैंकिंग जारी की

एजेंसी
नई दिल्ली। खान मंत्रालय ने गुरुवार को खनन क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खनन तत्परता सूचकांक (एसएमआरआई) और राज्य रैंकिंग जारी की है। इसके लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी। खान मंत्रालय के मुताबिक यह रैंकिंग राज्यों में खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सूचकांक को बनाने में नीलामी प्रदर्शन, शीघ्र खदान परिचालन, अन्वेषण पर जोर और गैर-कोयला खनिजों से संबंधित सतत खनन जैसे

संकेतक शामिल किये गए हैं, जो खनन क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन को रेखांकित करने के लिए प्रासंगिक हैं। मंत्रालय के मुताबिक एसएमआरआई के तहत राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी-ए में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हैं, जबकि श्रेणी बी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम शीर्ष तीन स्थान पर हैं। श्रेणी सी में पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा शीर्ष तीन स्थान पर हैं।

डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ रुपया, 72 पैसे की तेजी के साथ बंद हुई भारतीय मुद्रा

एजेंसी
नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती करने का संकेत देने और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का असर आज भारत के मुद्रा बाजार में साफ नजर आया। मुद्रा बाजार में बने सकारात्मक माहौल के कारण रुपया आज डॉलर की तुलना में मजबूती के साथ बंद हुआ। भारतीय मुद्रा आज डॉलर की तुलना में 72 पैसे उछल कर 88.08 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय मुद्रा 88.80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी।

रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी मजबूती के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 54 पैसे की तेजी के साथ 88.26 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के बाद स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपया ओपनिंग लेवल से 13 पैसे कमजोर होकर 88.39 के स्तर तक गिर गया। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को सहारा देने के लिए हस्तक्षेप करने की खबर ने मुद्रा बाजार को काफी प्रभावित किया। इस खबर की वजह से भारतीय मुद्रा 1.05

रुपये की मजबूती के साथ 87.75 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गई। हालांकि, बाद में रिजर्व बैंक की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होने पर रुपया इस स्तर से नीचे लुढ़कने लगा। पूरे दिन के कारोबार के बाद डॉलर की तुलना में रुपये ने 72 पैसे की तेजी के साथ 88.08 के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। मुद्रा बाजार के आज के कारोबार में रुपये ने डॉलर के साथ ही ज्यादातर दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले भी मजबूत प्रदर्शन किया। आज के कारोबार के बाद ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में रुपया 25.55 पैसे की तेजी के साथ 117.55 (अनंतिम) के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह यूरो की तुलना में रुपया आज 15.52 पैसे की बढ़त के साथ 102.44 (अनंतिम) के स्तर पर पहुंच कर बंद हुआ।

मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ पहले दिन 1.84 गुना हुआ सब्सक्राइब

एजेंसी
नई दिल्ली। क्वार्ट्ज प्रोसेसर मिडवेस्ट लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बोली लगाने के पहले दिन 1.84 गुना पूर्ण अभिदान प्राप्त (सब्सक्राइब) हुआ है, जो इस आईपीओ के लिए खुदरा और गैर-संस्थागत निवेशकों की ओर से जबरदस्त मांग को दर्शाता है। स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक क्वार्ट्ज प्रोसेसर मिडवेस्ट लिमिटेड के इस निर्गम को 31,17,460 इक्विटी शेयरों के मुकाबले 57,33,840 शेयरों की बोलियां प्राप्त हुईं। खुदरा और गैर-संस्थागत शेयरों को क्रमशः 1.60 गुना और 4.17 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। वहीं, योग्य संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) को 0.50 गुना और कर्मचारी शेयरों को 2.54 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। देश में ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी क्वार्ट्ज प्रोसेसर मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ आज को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला, जो शुक्रवार, 17 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। इश्यू खुलने से एक दिन पहले मिडवेस्ट लिमिटेड ने एंकर निवेशकों से 135 करोड़ रुपये

जुटाए थे। क्वार्ट्ज प्रोसेसर मिडवेस्ट लिमिटेड के 451 करोड़ रुपये के आईपीओ में 250 करोड़ रुपये का एक नया इश्यू और 201 करोड़ रुपये का एक ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी ने इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 1014-1065 रुपये प्रति शेयर तय किया है। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 24 अक्टूबर की जाएगी। क्वार्ट्ज प्रोसेसर मिडवेस्ट लिमिटेड न केवल क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग में अग्रणी है, बल्कि यह भारत की सबसे बड़ी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट उत्पादक कंपनी भी है। इस कंपनी के पास प्राकृतिक पत्थर उद्योग में 4 दशक से अधिक का अनुभव है, जो अपने व्यवसाय में स्थायित्व पर विशेष ध्यान देती है। यह भारत में ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो भारतीय खनन और निर्माण उद्योग की कैप्टिव खपत और बाजार की मांग, दोनों को पूरा करता है।

चांदी की चमक से सर्राफा बाजार हैरान, चेन्नई और हैदराबाद में चांदी 2.07 लाख रुपये के स्तर पर

एजेंसी
नई दिल्ली। सर्राफा बाजार में सोना और चांदी ने अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर दिया है। खासकर, चांदी के भाव में आए उछाल ने मार्केट एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। आज इस चमकीली धातु की कीमत हैदराबाद और चेन्नई में 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में चांदी 1,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है।इसके पहले आज दिल्ली में चांदी ने 1,89,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। इसी तरह चेन्नई और हैदराबाद में चांदी की शुरुआत 1,96,700 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से हुआ थी। दोपहर बाद चांदी की कीमत में तेजी का रुख बन गया। इस तेजी के साथ ही चांदी ने एक बार फिर

मजबूती का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी की कीमत एक ही दिन में 10 हजार रुपये से अधिक की छलांग लगाकर 2,07,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। चेन्नई और हैदराबाद के अलावा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, गुरुग्राम, लखनऊ, गाजियाबाद, जयपुर, पटना और भुवनेश्वर में चांदी शाम 6 बजे तक का कारोबार होने के बाद 1,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची हुई थी। दूसरी ओर, बेंगलुरु में चांदी की कीमत 1,93,700 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची हुई है। जानकारों का कहना है कि धनतेरस और दीपावली के पहले सर्राफा बाजार में जबरदस्त खरीदारी का रुख बना हुआ है। त्योहार और शादी विवाह के सीजन की जोरदार मांग के कारण चांदी रोज मजबूती का नया रिकॉर्ड बना रही है। खासकर गहने बेचने वाले रिटेल ज्वेलर्स की डिमांड ने सर्राफा बाजार में चांदी और सोने जैसे चमकीली धातुओं की कीमत को काफी तेज कर दिया है। बुलियन मार्केट एक्सपर्ट मयंक मोहन का कहना है कि भारत में त्योहारी और शादी विवाह का सीजन होने के साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में चांदी की बढ़ी हुई मांग ने भी इस चमकीली धातु की कीमत को और तेज कर दिया है।

दो दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी, शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद उछले सेंसेक्स और निफ्टी

एजेंसी
नई दिल्ली। लगातार दो दिनों तक कमजोरी का सामना करने के बाद घरेलू शेयर बाजार आज मजबूती के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई थी। पहले 1 घंटे के कारोबार में बाजार में उतार-चढ़ाव होता रहा, लेकिन इसके बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया। इस वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में तेजी आ गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.70 प्रतिशत और निफ्टी 0.71 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। माना जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती करने का संकेत देने, इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स (इंडिया वीआईएक्स) में गिरावट आने, कच्चे तेल के भाव में नरमी आने, डॉलर की तुलना में रुपये के मजबूत होने और मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से शेयर बाजार में आज पूरे दिन उत्साह का माहौल बना रहा। आज दिनभर के कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट के सभी सेक्टोरल इंडेक्स मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। रियल्टी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में आज सबसे अधिक खरीदारी होती रही। इसी तरह आईटी, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्युरेबल्स, एफएमसीजी, हेल्थकेयर, मेटल, ऑयल एंड गैस और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 1.07 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.78 प्रतिशत की तेजी के साथ आज के कारोबार का अंत किया।

एयर इंडिया 26 अक्टूबर से सर्दियों के दौरान शुरू करेगी 174 नई साप्ताहिक उड़ानें

एजेंसी
नई दिल्ली। टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया ने 26 अक्टूबर से उत्तरी शीतकालीन कार्यक्रम के तहत प्रमुख घरेलू और कम दूरी के अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 174 साप्ताहिक उड़ानें जोड़ने की घोषणा की है। एयर इंडिया इनका संचालन अपने सिंगल-आइल विमानों के जरिए करेगी। इन उड़ानों से भारतीय शहरों के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लोकप्रिय गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। एयरलाइंस ने जारी एक बयान में बताया कि नई उड़ानें शुरू करने से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। एयरलाइंस ने कहा कि 15 नवंबर से दिल्ली-कुआलालंपुर साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 7 गुना से बढ़ाकर 10 गुना की जाएगी। दिल्ली-देनपसार (बाली) के लिए एक दिसंबर से साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 7 गुना से बढ़ाकर 10 गुना कर दी गई है।

राजस्थान के लिए (26 अक्टूबर से) :-
दिल्ली-जयपुर (नया रूट), 3 उड़ानें रोजाना
दिल्ली-जैसलमेर (नया रूट), 2 उड़ानें रोजाना
दिल्ली-उदयपुर, 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना
मुंबई से राजस्थान के लिए फ्लाइट
मुंबई-जयपुर, 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना
मुंबई-उदयपुर, 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना
मुंबई-जोधपुर, 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना
मध्य प्रदेश के लिए
दिल्ली-इंदौर, 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना
दिल्ली-भोपाल, 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना
मुंबई-इंदौर, 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना
गुजरात के लिए फ्लाइट
मुंबई-भुज, 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना
दिल्ली-राजकोट, 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना
अन्य रूटों पर बढ़ीं उड़ानें
दिल्ली-वाराणसी, रायपुरः 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना
दिल्ली-पोर्ट ब्लेयर, औरंगाबाद, गुवाहाटी, नागपुरः 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना
मुंबई-देहरादून, पटना, अमृतसरः 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना
अंतरराष्ट्रीय रूट पर नई उड़ानें
दिल्ली-कुआलालंपुरः 7 से बढ़ाकर 10 उड़ानें प्रति सप्ताह (15 नवंबर से) और दिल्ली-देनपासार (बाली):7 से बढ़ाकर 10 उड़ानें प्रति सप्ताह (1 दिसंबर से) शुरू होगी।

एयर इंडिया ने कहा कि एयरलाइन ने अपने पुराने एयरबस-320ठ्ठद्भश विमानों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं। 27 में से 26 विमानों में अब नया इंटीरियर और तीन क्लास बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी की सुविधा है। एयरलाइंस के पास अब 100 से ज्यादा-320 फैमिली विमान हैं, जो 80 से ज्यादा घरेलू और शॉर्ट इंटरनेशनल रूट्स पर यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगे।

प्रधानमंत्री 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, उद्घाटन

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीशैलम स्थित प्रसिद्ध श्री भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके अलावा वे कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री सुबह नंदयाल जिले के श्रीशैलम स्थित प्रसिद्ध श्री भ्रमरम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानम में पूजा-अर्चना करेंगे। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहां एक ही परिसर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थित हैं, जिससे यह देशभर में अद्वितीय धार्मिक स्थल बनता है। प्रधानमंत्री इसके बाद श्रीशैलम स्थित श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे। यह केंद्र छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक स्मारक परिसर है, जिसमें ध्यान मंदिर के चारों कोनों पर उनके चार प्रमुख किलों–प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी–के मॉडल बने हैं। केंद्र में शिवाजी महाराज की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। यह स्मारक 1677 में शिवाजी महाराज की श्रीशैलम यात्रा की स्मृति में स्थापित श्री शिवाजी स्मारक समिति द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे, जहां दोपहर लगभग 2:30 बजे वे लगभग 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में उद्योग, सड़क, रेलवे, ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और आंध्र प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति देना है। प्रधानमंत्री 2,880 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कुरनूल-III पूलिंग स्टेशन पर पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे 6,000 एमवीए की परिवर्तन क्षमता बढ़ेगी और नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक विकास को बल देने के लिए, प्रधानमंत्री कुरनूल के ओर्वाकल औद्योगिक क्षेत्र और कडप्पा के कोप्पर्थी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला रखेंगे, जिन पर कुल 4,920 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इन परियोजनाओं से करीब एक लाख रोजगार सृजित होने और 21,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की संभावना है।

देश का निर्यात सितंबर में 6.74 फीसदी बढ़कर हुआ 36.38 अरब डॉलर

एजेंसी
नई दिल्ली। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सितंबर में देश का निर्यात 6.74 फीसदी बढ़कर 36.38 अरब डॉलर हो गया। आयात 16.6 फीसदी बढ़कर 68.53 अरब डॉलर रहा। इस दौरान व्यापार घाटा 32.1 अरब डॉलर रहा। सोना, चांदी, उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में इजाफा होने के कारण आयात में वृद्धि हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी आंकड़ों में बताया कि भारत का निर्यात सितंबर में

6.74 फीसदी बढ़कर 36.38 अरब डॉलर रहा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार आयात 16.6 फीसदी बढ़कर 68.53 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान देश का व्यापार घाटा 32.1 अरब डॉलर रहा है। सोना, चांदी, उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के आयात में वृद्धि के कारण आयात बढ़ा है। मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही अप्रैल-सितंबर के दौरान निर्यात 3.02 फीसदी बढ़कर 220.12 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान आयात 4.53 फीसदी बढ़कर 375.11 अरब डॉलर रहा।

कृषि को लाभकारी बनाने के लिए पीएमएफएमई, पीएमडीडीकेवाई का फायदा उठाएं किसान : सीतारमण

एजेंसी
नई दिल्ली/कोप्पल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदलने के लिए किसानों से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को संगठित क्षेत्र में लाने की योजना पीएमएफएमई और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) का पूरा लाभ उठाने की अपील की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कर्नाटक के कोप्पल जिले के मेथागल गांव में 'किसान प्रशिक्षण एवं साझा सुविधा केंद्र' का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि नई पीढ़ी के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार ग्रामीण और कृषि समुदायों के लिए भी फायदेमंद होंगे। इस केंद्र की स्थापना निर्मला सीतारमण के 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि' (एमपीएलएडी) से की गई है।

सीतारमण ने आगे कहा, दीर्घकालिक रूप से जब हम मूल्य संवर्धन की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) योजना तुरंत ध्यान में आती है। वित्?त मंत्री ने बताया कि पीएमएफएमई योजना कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है और उद्यमों को आधुनिक बनाने में मदद करती है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित कर गांवों में रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा, ''वर्ष 2020 से अब तक केंद्र सरकार ने राज्यों को 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। किसानों के लिए 11,000 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा

चुके हैं, जबकि एक लाख से अधिक कृषि उद्यमी सामने आए हैं।'' सीतारमण ने पीएमडीडीकेवाई योजना का जिक्र करते हुए कहा, ''वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोप्पल इस योजना से लाभान्वित होने वाले जिलों में से एक है।'' उन्?होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसलों का विविधीकरण प्रोत्साहित करना और 100 कम उत्पादक जिलों में किसानों की आजीविका सुधारना है। उन्होंने बताया कि जैव कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और जैव उर्वरकों पर भी जीएसटी दरों में कटौती की गई है।वित्त मंत्री ने बताया कि कर्नाटक के 43 लाख किसान 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के लाभार्थी हैं, जिसके तहत उन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तीन किस्तों में सीधे उनके खातों में दिए जाते हैं। सीतारमण ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर दिवाली से पहले जीएसटी परिषद ने नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार किए, जिसको नवरात्रि के पहले दिन लागू कर दिया गया। अब कृषि उपकरण, सौर ऊर्जा संयंत्र, ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर कर या तो हटा दिए गए हैं या 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिए गए हैं।''

देश का दर्पण न्यूज प्राइवेट लिमिटेड 14 नंबर वीकेआई सीकर रोड जयपुर राजस्थान मोबाइल नंबर 701499 7449/ 7878970109 deshkadarpannews.@gmail.com website - www.deshkadarpannews.co/www.deshkadarpannews.com